वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

1992-93

सत्यमेव जयते

भारतीय डाक विभाग

Department of Posts, India

विषय सूची

भाग 1 :	वार्षिक रिपोर्ट (1991-92)	
	पुनरीक्षा	3
	संगठन	7
	डाक प्रचालन	9
	डाक वित्त	16
	मानव संसाधन	20
भाग 2 :	वार्षिक रिपोर्ट (1992-93)	23

CONTENTS

Part 1 :	Annual Report (1991-92)	
	Overview	26
	Organisation	29
	Postal Operations	31
	Postal Finance	38
	Human Resources	42
Part 2 :	Annual Report (1992-93)	45
	Statistical Supplements	47

भाग - 1

वार्षिक रिपोर्ट

1991-92

पुनरीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष की विशेषता यह रही कि इसमें डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि विगत वर्षों में टेक्नालॉजी की शुरुआत में अपेक्षाकृत कम सक्रिय अवधि के बाद, वर्ष 1991-92 में आधुनिकीकरण के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए गए। टेक्नालॉजी की शुरुआत करने के कार्यक्रमों को दिशा देने व उन पर दृष्टि रखने के लिए संचार राज्य मंत्री द्वारा गठित स्टीयरिंग ग्रुप ने इस क्षेत्र में हुई प्रगति को मॉनीटर किया और मौजूदा तथा प्रस्तावित योजनाओं को आवश्यक प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार, डाक सेवाओं में आधुनिकीकरण के लिए जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया, उनमें वर्ष के दौरान संतोषजनक प्रगति परिलक्षित हुई।

डाकघर कम्प्यूटरीकरण

किसी डाक-मद पर देय डाक शुल्क, जो डाक-मद के वजन और श्रेणी पर निर्भर करता है, उसकी संगणना के लिए माइक्रो-प्रोसेसर में प्रोग्रेम्ड मेमोरी का प्रयोग करने से किसी काउन्टर पर लेन-देन पूरा करने में जितना समय लगता है, इससे उसे कम करने में मदद मिलती है। एक ही काउंटर से विभिन्न प्रकार के डाक कार्य सम्पादित करने का उद्देश्य पी.सी. पर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीन की अवधारणा से प्राप्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर मेंटेनेन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सी.एम.सी) और ब्राडमा इंडिया लिमिटेड द्वारा ऐसी मशीनों के लिए हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर विकसित किया गया था और इसका प्रारंभ वर्ष 1991 में मुख्य शहरों के 22 चुनिंदा डाकघरों में 102 मशीनें स्थापित करके किया गया था। इन मशीनों की कार्य-प्रणाली के फीडबैक से पता चलता है कि काउन्टर पर प्रतीक्षा समय कम करने और एक ही काउंटर पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के अलावा इस मशीन पर कार्यरत एक आपरेटर सामान्यतः काफी बड़ी संख्या में लेन-देन करता है जबकि उस कार्य को हाथों से उतने ही समय के भीतर दो काउन्टर सहायकों द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार, इन मशीनों से उपभोक्ता संतुष्टि का तत्व भी निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1992-93 में विभिन्न डाकघरों को 1000 अतिरिक्त कम्प्यूटरीकृत काउन्टर मशीनों की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों को आर्डर दिये गये हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम से कम ऐसी 5000 मशीनें स्थापित करने का विभाग का प्रस्ताव है।

दिल्ली सर्किल के 7 प्रधान डाकघरों में बचत बैंक कार्य के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति भी संतोषजनक रही। गौरतलब है कि दिल्ली में पहली बार बचत बैंक कम्प्यूटरीकरण स्कीम सन् 1986 में शुरु की गई थी। कुछ प्रधान डाकघरों में पहले से प्रदान की गयी प्रणाली के उन्नयन सहित आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश के कम-से-कम 21 प्रधान डाकघरों में इस कार्य का कम्प्यूटरीकरण करने का विचार है।

जहां तक डाक जीवन बीमा का संबंध है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात सर्किलों में मौजूदा प्रणाली का इस सीमा तक उन्नयन करने का प्रस्ताव है जिससे अधिकाधिक डाक जीवन बीमा पालिसियों तथा लेन-देन से संबंधित कार्य बड़ी संख्या में हो सके। सन् 1994 तक शेष सभी सर्किलों

में पी.एल.आई. कार्य का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार कम्प्यूटरीकरण का धीरे-धीरे विकास होने से स्टाफ उत्संस्करण, अनुकूल क्षमता, अधिक अभिप्रेरणा तथा उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि होगी।

उल्लेखनीय है कि आधुनिकीकरण की सभी योजनाएं यूनियनों के साथ परामर्श करके कार्यान्वित की जाती हैं।

मशीनी छंटाई

पिछली रिपोर्ट में डाक विभाग और बेल्जियम की अल्काटेल बैल कम्पनी के बीच एक समझौते पर हुए हस्ताक्षर का उल्लेख किया गया था। इस समझौते के अन्तर्गत बंबई में एक ऑटोमैटिक इंटीग्रेटिड मेल प्रोसेसिंग सिस्टम की स्थापना की जानी थी। इस उपस्कर में दो कम्प्यूटरीकृत पत्र छंटाई मशीनें और नियंत्रण सुविधा सहित 6 स्यूट्स में 30 हस्तचालित कोडिंग डेस्क हैं। यह उपस्कर बंबई में प्राप्त हो गया है और स्थापित किया जा रहा है। इसके एक्सेपटिंग टैस्टिंग का कार्य चल रहा है। ऐसी संभावना है कि यह प्रणाली मार्च, 1993 तक स्थापित हो जाएगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में तीन प्रणालियां स्थापित करने का विचार है। दूसरी प्रणाली 1993-94 के दौरान मद्रास में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

उपग्रह मनीआर्डर सेवा

सरकार ने उपग्रह संचार के जरिये मनीआर्डर भेजने के लिए 75 माइक्रो-अर्थ स्टेशन (वैरी स्मॉल एपीचर टर्मिनल्स वी.एस.ए.टी. भी कहा जाता है) स्थापित करने की योजना का अनुमोदन कर दिया है।

इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग सभी आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस नई तकनीक से मनीआर्डर प्रचालन की लागत घटने की आशा है। इस प्रकार विकसित नेटवर्क विभाग को भविष्य में नवीन वैल्यू एडिड सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रानिक मनी ट्रांसफर, जी.आई.आर.ओ., संदेश संचारण आदि शुरु करने में भी मदद देगा। इन सेवाओं में सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने की भी पर्याप्त क्षमता है।

डाक-टिकट, मुहर और डाक मशीन

हमारे अधिकांश डाकघरों में अब 400 वस्तुएं प्रति मिनट निपटाने की क्षमता वाली उच्चगति की डाक विरूपण मशीनों के अलावा 150 वस्तुएं प्रति मिनट निपटाने की क्षमता वाली कम गति की डाक-टिकट विरूपण मशीनें कार्य कर रही हैं। ऐसी 60 मशीनों के सफल संचालन के प्रारंभिक प्रयोग के पश्चात् डाकघरों हेतु ऐसी 270 मशीनों की आपूर्ति का विभाग का प्रस्ताव है। विभाग ने विरूपण के लिए मशीन से खुदी स्टील की हाथ की मुहरों के निर्माण के आदेश दिये हैं। विभाग ने ठोस स्टील की एनग्रेव्ड मुहरों के निर्माण के लिए आर्डनेंस फैक्ट्री के महानिदेशक और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि. से बातचीत की है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंकिंग मशीनों के संबंध में विभाग ने इस देश की विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित 7 विभिन्न माडलों का अनुमोदन किया है। फ्रेंकिंग मशीन के कम्प्यूटरीकृत माडल के अनुमोदन की भी जाँच की जा रही है।

नेटवर्क का विस्तार

पिछली रिपोर्ट में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर खोलने के नये मानदंड लागू करने का उल्लेख किया गया था। डाकघर खोलने में तेजी लाने के लिए सरकार ने ऐसे डाकघर खोलने की शक्तियां सर्किल अध्यक्षों को प्रदान कर दी हैं जो मानदंडों को पूरा करते हैं। तथापि अब तक

चलाये गये डाक विस्तार कार्यक्रम का मूल्यांकन करना जरूरी है ताकि यह देखा जा सके कि ग्रामीण विकास में यह कहां तक प्रभावी रहा है और उन डाकघरों को भी बंद किया जा सके जिनसे विभाग को निरंतर घाटा हो रहा है। परंपरागत प्रणाली के स्थान पर नई प्रणाली प्रारंभ करने के प्रश्न पर भी विभाग ध्यान दे रहा है जिसके अंतर्गत लाइसेंसशुदा एजेंट ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में डाक कार्य कर सकते हैं।

एशिया प्रशांत डाक संघ (अप्पू)

एशिया प्रशांत डाक संघ की कार्यकारिणी परिषद् की बैठक 15 सितम्बर, 1992 से 21 सितम्बर, 1992 तक नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। इस बैठक में विश्व के बदले हुए आर्थिक और व्यापारिक परिदृश्य के कारण अप्पू के सदस्य देशों के सामने आए मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। वाशिंगटन सामान्य कार्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सदस्य देशों द्वारा की गई प्रगति की भी समीक्षा की गई। नई दिल्ली संकल्प, सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसे विश्व डाक संघ के प्रति निष्ठा के समर्थन में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और यू.पी.यू. की परंपराओं को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

साल सर्विस

सरफेस एअर लिफ्टिड (साल) डाक सेवा की शुरुआत अपने ग्राहकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विविध सेवाएं प्रदान करने और उन्हें अधिक से अधिक संतोष प्रदान करने के विभाग के संकल्प के अनुरूप है। आरंभ में "साल" सेवा भारत से चार अन्य देशों अर्थात्, यू.के., यू.एस.ए., जर्मनी और सिंगापुर के साथ शुरु करने का निर्णय लिया गया है। "साल" डाक एयर इंडिया द्वारा ले जाई जाएगी जिसने डाक भाड़े में 50 प्रतिशत छूट देना स्वीकार और भारतीय मुद्रा में भुगतान स्वीकार करना स्वीकार किया है। एयर इंडिया ऐसी डाक को सप्ताह में एक बार ले जाएगी। इस व्यवस्था से पारेषण समय में गुणात्मक अंतर आएगा। "साल" डाक सेवा प्रारंभ होने से पहले भारत से इन चार देशों के लिए भूतल डाक औसतन दो से तीन महीने में पहुंचती थी। नई सेवा से इन देशों के लिए भूतल डाक औसतन दस दिनों में पहुंचनी संभव हो सकेगी। "साल" मेल को प्रेषक देश से विनिमय कार्यालय तक और गंतव्य देश के विनिमय कार्यालय से वितरण केन्द्र तक भूतल डाक माना जाएगा लेकिन इसे दोनों देशों के बीच हवाई डाक से भेजा जाएगा। इस प्रयोग के सफल होने पर दूसरे देशों में इसका विस्तार किया जाएगा।

फिलैटली

इस अवधि में नियत डाक-टिकटों के साथ-साथ स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाते रहे। इस अवधि में भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती, भारतीय वायुसेना की स्वर्ण जयंती तथा पक्षियों की लुप्त होती प्रजाति तथा दूसरे विभिन्न विषयों पर डाक-टिकट जारी किए गए जिन्होंने एक चित्ताकर्षक और विभिन्न विषयों का स्वस्थ संगम प्रस्तुत किया। डाक स्टेशनरी में सुधार लाने के प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न रंगों के अंतर्देशीय कार्ड तथा पोस्टकार्ड जारी किए गए। नए रंग काफी लोकप्रिए हुए। मशीनी प्रक्रिया के अधिक अनुरूप बनाने के लिए बड़े फार्मेट के ऐसे अंतर्देशीय पत्र-कार्ड भी शीघ्र तैयार किए जाएंगे जो सभी तरफ से बंद होंगे और इस प्रकार भारत में डाक के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात होगा। अत्याधिक उपभोक्ता संतुष्टि के लिए फिलैटलिक मदों के विविध उत्पादन के लिए कई अन्य कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं।

व्यय-राजस्व अंतर

वर्ष 1991-92 में विभाग का कुल

कार्यकारी व्यय 1162.15 करोड़ रु. था जिसकी तुलना में राजस्व-आय 947.87 करोड़ रुपये था। इस प्रकार अंतर 214.28 करोड़ रुपये रहा। हालांकि व्यय को नियंत्रित करने के प्रयास किये गए लेकिन दरों में संशोधन की अपेक्षा बेहतर प्रबंध द्वारा राजस्व की वृद्धि सुनिश्चित की गई । अपने कर्मचारियों की नियमित वेतन वृद्धि के बावजूद जून, 1990 से घरेलू डाक दरों में संशोधन नहीं किया गया है। तथापि, नवम्बर, 1991 के माह में विदेश डाक दरों में कुछ परिवर्तन किये गये थे। विभाग ने अनुकूल स्तर तक कार्य-क्षमता में सुधार करके घाटा कम करने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण और संगठनात्मक सुधार पर जोर दिया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

सरकार ने विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कर दिया है । इस योजना में टेक्नालॉजी पर मुख्य रूप से बल दिया गया है जिससे सातवीं योजना के दौरान प्रारंभ किये गये विभिन्न कार्यक्रमों को जारी रखकर तथा विस्तार करके सुनिश्चित किया जायेगा। सरकार ने संपूर्ण योजना अवधि के लिए 325 करोड़ रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी है।

भविष्य के कार्यक्रम

यह सुनिश्चित करने के लिए कि तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए तथा साथ ही डाक सेवाओं के प्रति बढ़ती जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभाग को पुनः स्फूर्तिवान बनाने के लिए संचार मंत्री ने मार्च, 1992 में एक सोशल ऑडिट पैनल का गठन किया। इस पैनल के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी.एन. भगवती हैं। डॉ.एन.के. भास्कर राव इसके संयोजक सदस्य हैं । श्री खुशवंत सिंह, वाइस एडमिरल एस. चोपड़ा (सेवानिवृत्त), एयर चीफ मार्शल जे.के.सेठ (सेवानिवृत्त) तथा बी.जी. देशमुख, कैबिनेट सेक्रेटरी (सेवानिवृत्त) इस पैनल के सदस्य हैं। इस पैनल ने डाक सेवाओं की स्थिति के बारे में जनता के विचार जानने तथा उनमें सुधार हेतु सुझाव और विचार प्राप्त करने के लिए महानगरों तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों में 20 से अधिक ओपन हाउस आयोजित किये। पैनल ने डाक वितरण, स्पीड पोस्ट नैटवर्क के विस्तार, आधुनिकीकरण, एजेंसी कार्यों के आधुनिकीकरण तथा डाक सेवा बोर्ड के संगठन तथा कार्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बोर्ड द्वारा इन रिपोर्टों की जाँच की जा रही है।

भारतीय डाकघर अधिनियम जो भारत में डाकघर को एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है, लगभग 100 वर्ष पुराना है और समय-समय पर इसमें व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गई है । अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली तथा देश के आर्थिक परिदृश्य में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं जिन्हें अधिनियम में परिलक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार ने डाक सेवा बोर्ड के एक सेवानिवृत्त सदस्य, श्री गुरुचरण सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल करके भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की जाँच और आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति ने अपना विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

भविष्य में डाक सेवाओं के विकास में सोशल ऑडिट पैनल के अलावा भारतीय डाकघर अधिनियम में परिवर्तन के लिए गठित समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा। डाक विभाग जनता के प्रति अपनी कार्यकुशल और निःस्वार्थ सेवा भावना की अपनी परम्परा से आधुनिक भारत के सामाजिक आर्थिक परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर है।

संगठन

तत्कालीन डाक-तार विभाग का विभाजन करने के पश्चात् जनवरी, 1985 में डाक विभाग का सृजन किया गया था। यह संचार मंत्रालय का एक अंग है। विचाराधीन अवधि के दौरान मंत्रालय श्री राजेश पायलट, संचार राज्य मंत्री के नियंत्रण में था। श्री पी.वी. रंगय्या नायडू, संचार उप-मंत्री थे। 18 जनवरी, 1993 को श्री सुखराम ने संचार राज्य मंत्री का पदभार सम्भाला।

मुख्यालय

विभाग की प्रबन्ध व्यवस्था डाक सेवा बोर्ड करता है, जिसमें एक अध्यक्ष और तीन सदस्य हैं। सचिव, डाक विभाग, डाक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वे महानिदेशक, डाक भी हैं। सदस्यों को प्रचालन, विकास और कार्मिक के कार्य सौंपे गए हैं। इसके अतिरिक्त एक वित्तीय सलाहकार भी हैं। बोर्ड की सहायता के लिए सचिव, डाक सेवा बोर्ड हैं। डाक महानिदेशक में सोलह उप महानिदेशकों की सहायता से बोर्ड देश में डाक सेवाओं के प्रबन्ध का निर्देशन और पर्यवेक्षण करता है।

सर्किल

विभाग के प्रचालन दायित्वों को निभाने के विचार से पूरे देश को 19 सर्किलों में बांटा गया है। एक सर्किल में एक अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल होते हैं। सर्किल के अध्यक्ष मुख्य पोस्टमास्टर जनरल होते हैं। सर्किलों को सामान्यतः क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों में डाक डिवीजनों के अनेक ग्रुप हैं। क्षेत्र में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को उच्चस्तरीय प्रबन्ध सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक पोस्टमास्टर जनरल है। सर्किलों के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास स्थित क्षेत्रीय डाक योजना इकाइयां पोस्टमास्टर जनरल के स्तर के नियंत्रकों के अधीन हैं। नियंत्रक डाक प्रचालनों के कार्य में बेहतर व्यावसायिकता लाते हैं। सर्किल में मेल डिवीजन, स्टोर डिपो, स्टैम्प डिपो और मेल मोटर सेवा जैसे अन्य कार्यात्मक डिवीजन और यूनिटें हैं।

भारतीय डाकघरों की मुख्य डाकघर, उप डाकघर और शाखा डाकघरों जैसी श्रेणियां हैं। शाखा डाकघर अधिकतर अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं तथा ये ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उप डाकघर अधिकतर विभागीय डाकघर हैं। मुख्य डाकघरों को उनके आकार के अनुसार पाँच श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से सबसे बड़े डाकघर, मुख्य डाकघर, बम्बई और मुख्य डाकघर, कलकत्ता हैं। इनके बाद मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलूर, कानपुर, लखनऊ और देश के अन्य बड़े शहरों में स्थित मुख्य डाकघरों का स्थान है।

सेना डाक सेवा के अध्यक्ष मेजर जनरल होते हैं, जिन्हें अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा का पदनाम दिया गया है। उन्हें मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, सेना डाक सेवा सर्किल भी कहा जाता है।

स्थिति

31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, डाक सेवा बोर्ड में श्री एस.पी. गुलाटी, सचिव (डाक), महानिदेशक, डाक और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड, श्री एस.के.एन. नायर, सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग जो डाक सेवा बोर्ड में सदस्य (वित्त) का कार्य देख रहे थे और श्री एल.डी. बोनेल, सदस्य (कार्मिक) थे। श्री एस.पी. गुलाटी के सेवानिवृत्त होने पर श्री एल.डी. बोनेल ने दिनांक 01-06-1992 को सचिव (डाक) का पदभार ग्रहण किया तथा 31.10.1992 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर आसीन रहे। श्री एस.के. पार्थसारथी जो 11.06.92 से सदस्य (कार्मिक) के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने 31.10.1992 को सचिव (डाक) का पदभार ग्रहण किया और अभी भी इसी पद पर आसीन हैं। फिलहाल बोर्ड में श्री एम.एस. राघवन, सदस्य (कार्मिक) हैं, श्री टी.ई.रमन, सदस्य (प्रचालन) और श्री एस.आर.फारूकी, सदस्य, (विकास) हैं। श्री वाई.एल. राजवाड़े, सचिव, डाक सेवा बोर्ड हैं। श्री जी.एस. राजामणि, वित्तीय सलाहकार डाक विभाग हैं तथा बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय डाक सम्बन्ध

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यू.पी.यू.) और एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (ए.पी.पी.यू.) के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय डाक मामलों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। इन दोनों संगठनों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, यथा-यू.पी.यू. के अन्तर्गत वाशिंगटन सामान्य कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए डाक अध्ययन की सलाहकार परिषद् (सी.सी.पी.एस.) की समिति -7 का अध्यक्ष और तकनीकी सहयोग तथा एशियन पैसिफिक पोपुलेशन (ए.पी.पी.यू.) की सहायता विषयक स्थायी समिति का अध्यक्ष है। सी.सी.पी.एस. के सदस्य के रूप में भारत सी.सी.पी.एस. द्वारा किए जा रहे विभिन्न अध्ययनों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। सी.सी.पी.एस. की समिति -7 के अध्यक्ष के रूप में भारत संचालन समिति का भी सदस्य है। सी.सी.पी.एस. द्वारा किए जा रहे विभिन्न अध्ययनों की प्रगति पर समिति विचार-विमर्श करती है तथा इसके कार्य की

भविष्य की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती है। यू.पी.यू. के सदस्य देशों के लिए भारत ने वरिष्ठ डाक प्रबंध पाठ्यक्रम आयोजित किया (18 नवम्बर, 1991 से 14 दिसम्बर, 1991 तक) । अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, चीन, फिजी, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपिन्स, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया ।

डाक विभाग ''सार्क'' की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । श्री विवेक कौल, सहायक महानिदेशक काठमांडू (11-12 जून, 1991) में डाक सेवाओं के संबंध में हुई तकनीकी समिति की दसवीं बैठक में शामिल हुए । श्री एस.एस. राय, निदेशक (डाक) अप्रैल, 1991 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित एक सार्क अध्ययन भ्रमण ''नई डाक और वित्तीय सेवाएं'' में शामिल हुए । श्री वाई.पी.एस. मोहन जून, 1991 में श्रीलंका में सार्क देशों के ''डाकप्रचालन और भविष्य की चुनौतियों'' पर सेमिनार में शामिल हुए । पोस्टल स्टाफ कॉलेज, भारत में सार्क सदस्य देशों के लिए 4-10 मार्च, 1991 तक ''ग्राहकों की देखरेख'' पर एक सार्क कार्यशाला आयोजित की गई । श्री के.बी.एच. नायर, प्राचार्य, डाक प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर जून, 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका में यू.पी.यू. द्वारा प्रायोजित सलाहकार मिशन के अन्तर्गत डाक सुरक्षा पाठ्यक्रम में शामिल हुए। श्री विनीत पांडे 28 अक्तूबर, 1991 से 8 नवम्बर, 1991 तक ब्रेमेन (जर्मनी) में यू.पी.यू. द्वारा प्रायोजित सलाहकार मिशन के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक डाक पर एक प्रायोगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अध्ययन भ्रमण में शामिल हुए ।

डाक प्रचालन

प्रस्तावना

डाक प्रचालन का प्रायः एक ही कार्य समझा जाता रहा है, पत्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरण करना । वास्तव में यह कार्यों के अन्तः संबंधों की बहुरंगी कड़ी है, जैसे पंजीकरण, मनीआर्डर, स्पीड पोस्ट, डाक-डिकटों की बिक्री, पोस्टल ऑर्डर आदि। इस प्रचालन की सफलता अक्सर परिवहन क्षेत्र की दूसरी एजेंसियों जैसे एयरलाइन, रेलवे, रोडवेज, शिपिंग आदि पर निर्भर करती है । डाकघर दूसरे मंत्रालयों/विभागों के कार्य, जैसे बचत बैंक और डाक जीवन बीमा आदि केकार्य भी करता है जो एजेंसी कार्य के नाम से जाने जाते हैं ।

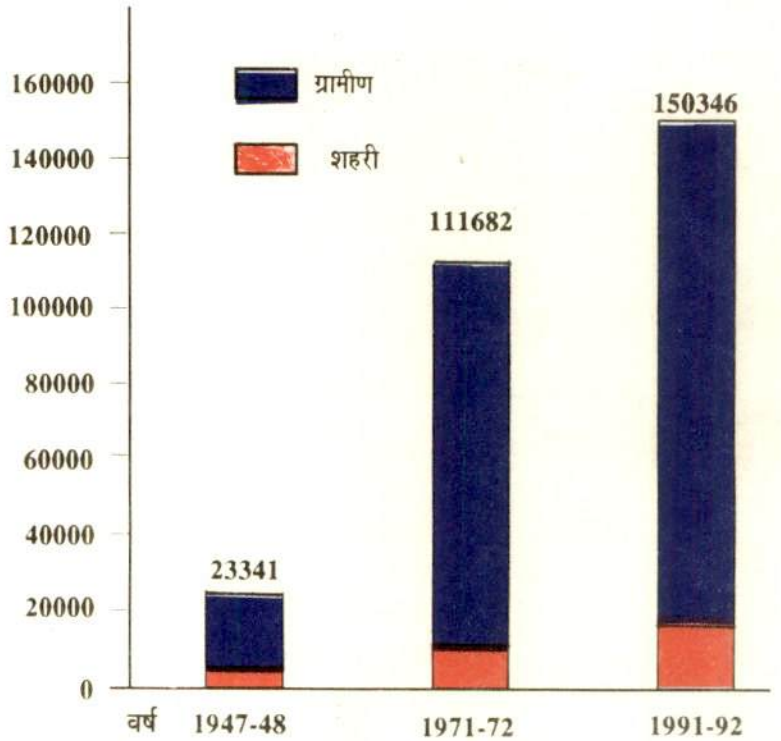

डाक नेटवर्क का विस्तार

तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए एक कुशल डाक प्रणाली आवश्यक है । भारत ने इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है और इसका डाक नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े डाक नेटवर्कों में से एक है । 31.3.92 तक देश में 150346 डाकघर थे जिनमें से 134122 ग्रामीण क्षेत्रों में थे। 1991 की जनगणना के अनुसार एक डाकघर औसतन 21.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 5827 जनसंख्या वाली आबादी को सेवा प्रदान करता था । 1991-92 के दौरान 2068 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों और 21 विभागीय उप डाकघरों की मंजूरी दी गई ।

सेवाएं

प्रदत्त की जाने वाली डाक सेवाएं

डाक सेवाएं

जैसे पत्र, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: लिफाफे, लेटर-कार्ड, पोस्टकार्ड बुक पैकेट, न्यूजपेपर, पैकेट पार्सल

इनका वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है:

साधारण डाक
पोस्टिंग सर्टिफाइड
आर्डीनरी मेल
रजिस्ट्रेशन
वैल्यूपेएबल
बीमा
स्पीड पोस्ट

धन अंतरण सेवाएं

जैसे मनीआर्डर
पोस्टल आर्डर

अन्य सेवाएं,

अर्थात् बचत बैंक
डाक जीवन बीमा
तार
टेलीफोन पब्लिक काल आफिसेज़
टेलीफोन रेवेन्यू कलेक्शन
पासपोर्ट आवेदन पत्र
केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट

डाक मात्रा

वर्ष के दौरान 3191 मिलियन अंतर्देशीय गैर-पंजीकृत डाक मदों का निपटान किया गया, जिसमें 2716 मिलियन पत्र, 435 मिलियन पैकेट और 40 मिलियन पार्सल सम्मिलित हैं। अंतर्देशीय पंजीकृत डाक की संख्या 296 मिलियन है ।

डाक विभाग ने वर्ष के दौरान 105.6 मिलियन मनीआर्डरों के भुगतान किए जिनका कुल योग 25872 मिलियन रुपए था । पोस्टल आर्डर के जरिए कुल 287.7 मिलियन रुपयों का भुगतान किया गया ।

1982-83 से डाक परियात
(राजस्व में समायोजित)

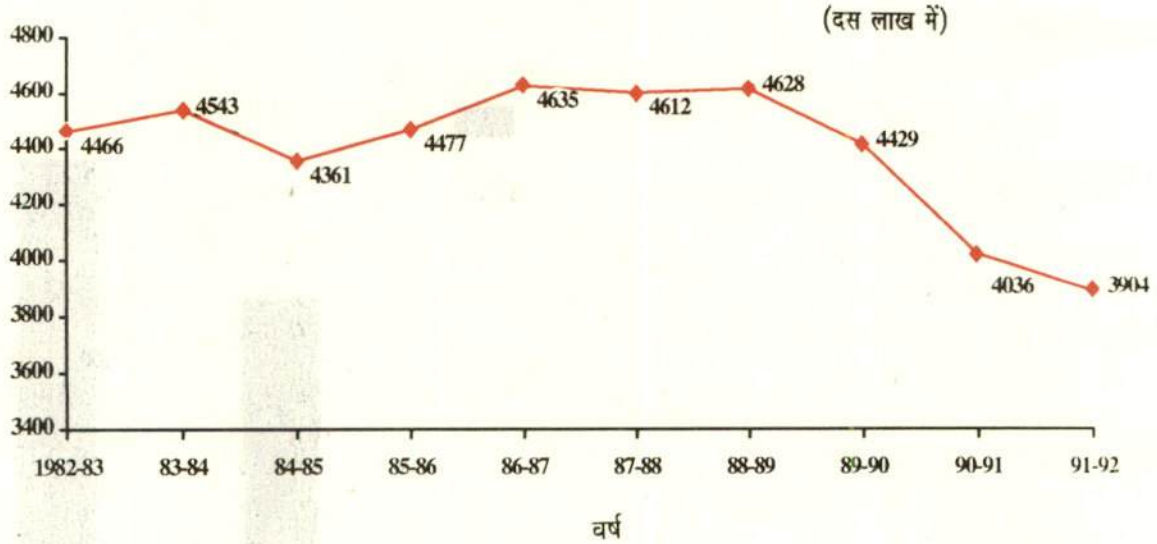

मदवार डाक परियात

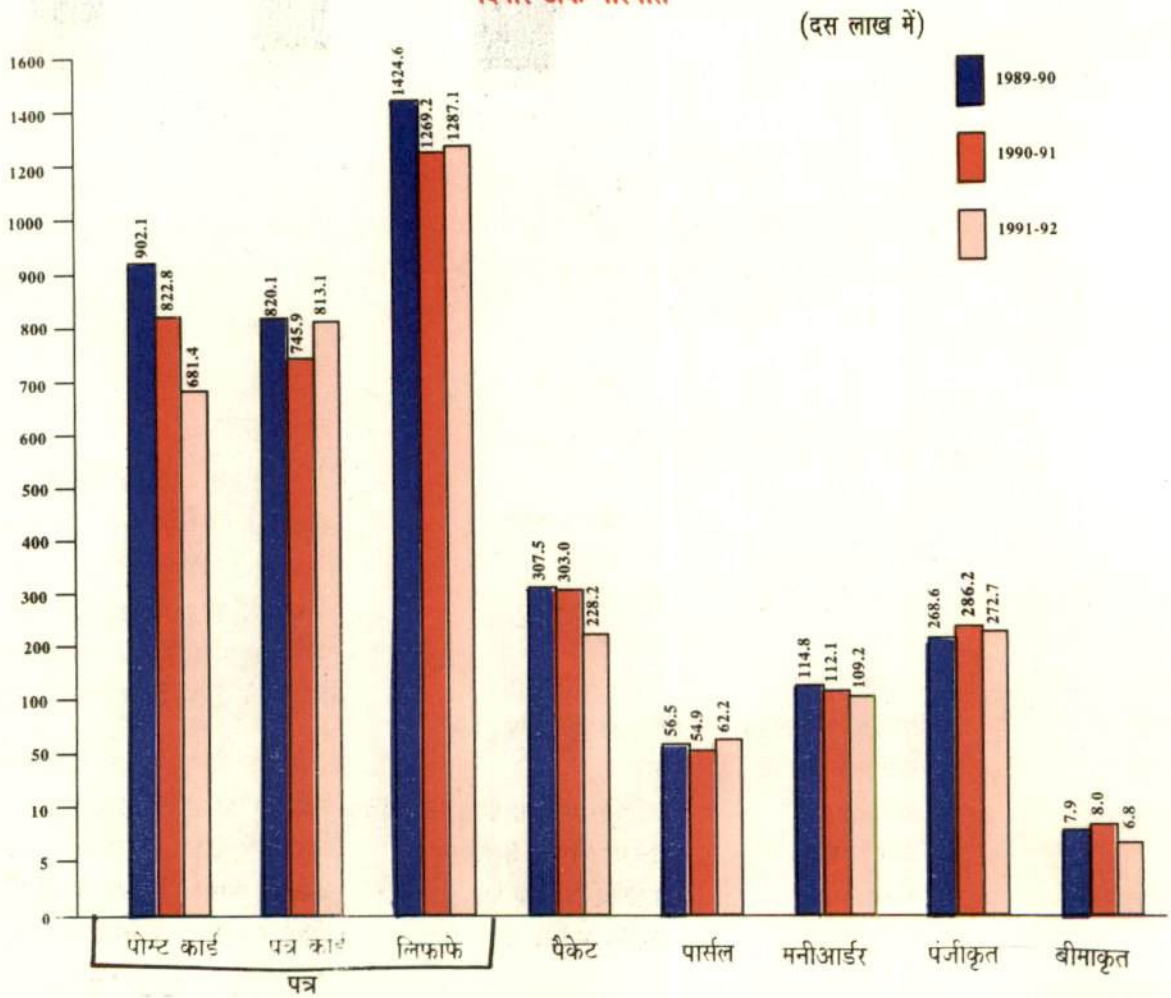

स्पीड पोस्ट

वर्ष 1991-92 में गुड़गांव (हरियाणा) में एक काउंटर खोला गया जिससे राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत स्पीड पोस्ट एक्सटेंशन काउंटरों की संख्या बढ़ गई । जो ग्राहक दो विशेष शहरों के बीच डाक का प्रेषण चाहते थे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्वाइंट टू प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा में 214 युग्म स्टेशन जोड़े गए । इसी प्रकार भारत भर में विस्तृत नेटवर्क के साथ विशेष वितरण व्यवस्था के द्वारा समष्टि ग्राहकों की मांगें पूरी करने के लिए निजीकृत स्पीड पोस्ट ठेका सेवा का विस्तार किया गया। 1.4.91 से मलावी, साइप्रस, कनाडा, इथोपिया, न्यूजीलैंड और सूडान के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सम्पर्क स्थापित किए गए ।

पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्पीड पोस्ट परियात में 35.80% की वृद्धि हुई । स्पीड पोस्ट राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 59.71% की वृद्धि हुई ।

वर्ष 1992-93 के दौरान स्पीड पोस्ट निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेगी:-

(क) वस्तुओं के वितरण की तत्काल सूचना पुष्टि, शिकायतें/धन वापसी के दावे और बेहतर ग्राहक संबंध बनाने के लिए कम्प्यूटरीकृत और मैनुअल ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली की स्थापना.....

(ख) वितरण में विलंब होने की दशा में स्पीड पोस्ट फीस की पूरी वापसी करना ।

(ग) डाक अवकाश (राष्ट्रीय अवकाश) स्पीड पोस्ट वस्तुओं का वितरण ।

(घ) स्पीड पोस्ट नेटवर्क की विस्तार योजना का विकास; और

(ङ) सभी स्पीड पोस्ट केन्द्रों द्वारा मानक स्पीड पोस्ट फार्मों का प्रयोग।

स्पीड़ पोस्ट परियात

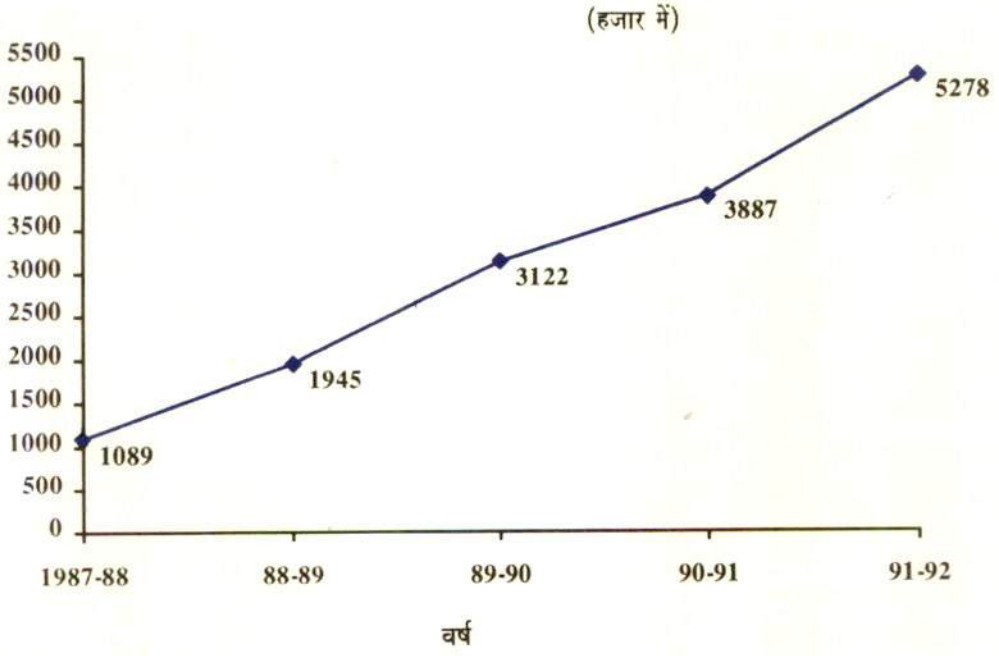

प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन

डाक छंटाई का मशीनीकरण डाक विभाग में प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। हाल ही में बंबई महानगर के लिए आवक और जावक डाक की मशीन द्वारा छंटाई की योजना विकसित की गयी थी। दिनांक 1.1.92 को स्वचालित एकीकृत डाक छंटाई प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन और चालू करने के संबंध में विभाग द्वारा बेल्जियम की अल्काटेल बैल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस मशीन को मार्च, 1993 के अंत तक चालू किए जाने की संभावना है।

पिछले वर्ष संस्थापित की गई पी.सी. पर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों के प्रयोग और मूल्यांकन के आधार पर विभाग द्वारा ऐसी और मशीनें संस्थापित करने का निर्णय लिया गया था। विभिन्न राज्यों के डाकघरों में 1000 और काउंटर मशीनों की आपूर्ति के लिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों को आर्डर दिए गए हैं।

इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के अतिरिक्त डाक प्रचालनों के उन अन्य क्षेत्रों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जहां सेवाओं में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है।

मेल मोटर सेवा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान देश के 90 स्टेशनों में विभागीय मेल मोटर सेवा कार्यरत रही। बेड़ों के सुधार और डाक लाने और ले जाने में कुशलता बनाए रखने के लिए मौजूदा वाहनों को बदलने के लिए 21 नए वाहन खरीदे गए।

वर्ष 1991-92 के अंत तक मेल मोटर के बेड़े की कुल संख्या 1103 थी और बेड़े द्वारा कुल 190 लाख किलोमीटर की दूरी दय की गई।

प्रणाली में परिवर्तन

मेल बाक्स योजना

विभाग को बहुमंजिला भवनों में डाक के वितरण की व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि उनकी संस्था न केवल बड़े शहरों में बल्कि, मध्यम आकार के नगरों में भी बढ़ रही है। डाकिए को पूरी डाक के साथ एक के बाद दूसरी अनेक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इससे डाकिए को डाक बांटने में विलंब होता है। अतः, यह आवश्यक हो गया कि गैर-पंजीकृत डाक को हरेक दरवाजे पर वितरित करने की परम्परा समाप्त की जाए, उसके लिए बहुमंजिला भवनों के भूतल पर व्यवस्था की जाए; जो अन्य तलों पर रहते हैं वे भूतल पर मेल बॉक्स उपलब्ध कराएं, जो हर व्यक्ति या पते के लिए पृथक अथवा एक से अधिक पतों के लिए संयुक्त रूप में हो सकते हैं। भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 21 के अधीन 29 मई, 1991 को एक विधिक आदेश जारी किया गया और निम्नलिखित श्रेणियों की डाक को इस आदेश की परिधि में लाया गया।

- पत्र डाक अर्थात् लिफाफा, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, पोस्टकार्ड और एयरोग्राम
- बुक, पैटर्न और नमूना पैकेट
- पावती कार्ड
- पंजीकृत समाचार-पत्र

यह आदेश 1 जनवरी, 1992 से लागू किया जाना था। किन्तु, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि इस तारीख के पश्चात् परिस्थितिवश आवश्यक होने पर डाक का वितरण किसी भी स्टेशन पर परंपरागत ढंग से जारी रखा जा सकता है।

रात्रि डाकघर में विलंब शुल्क

रात्रि डाकघर जनता के लिए विशेष सुविधा है। विभाग यह अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रात्रि डाकघरों के प्रचालन पर अतिरिक्त व्यय करता है। रात्रि डाकघर में निर्धारित घंटों के दौरान दी गई डाक के लिए विलंब शुल्क वसूल किया जाता है। अब साप्ताहिक दिनों और अवकाश तथा रविवार के दिनों में बढ़ाए गए घन्टों में दी गई गैर-पंजीकृत और पंजीकृत डाक पर विलंब शुल्क देना होगा। यह फीस समय-समय पर निर्धारित शुल्क दरों के अनुसार होगी।

डाक मदों का बीमा

बीमा की सीमा 14 सितम्बर, 1991 से 10,000 रु. से बढ़ाकर 20,000/- रु. कर दी गई थी।

फिलैटली

इक्यावन (51) स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी किए गए थे, जिनमें से एक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के सम्मान में 14 अप्रैल, 1991 को और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी पर स्मारक टिकट 20 अगस्त, 1991 को जारी किया गया। चार बहुरंगीय डाक-टिकटों का एक सेट जनजातीय नृत्यों पर जारी किया गया। आस्ट्रियन कम्पोज़र मोज़ार्ट पर डाक-टिकट अधिक लोकप्रिय हुआ। पूरे देश में फिलैटिस्टों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अब 50 फिलैटलिक ब्यूरो और 171 फिलैटलिक काउंटर हैं। दिनांक 24.1.92 को रायपुर में नया ब्यूरो खोला गया।

वर्ष के दौरान विभाग ने हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और पटना, बिहार में सर्किल स्तर की फिलैटलिक प्रदर्शनियाँ आयोजित की थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभाग ने अगस्त, 1991 में बैंकाक में, मार्च, 1992 में मांट्रियल में, 8 अगस्त से 29 अगस्त, 1991 तक पेरू में और 21 अक्तूबर से 25 अक्तूबर, 1991 तक बोन में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लिया।

सभी प्रकार की बचतों, बचत पत्रों सहित बकाया इतिशेष

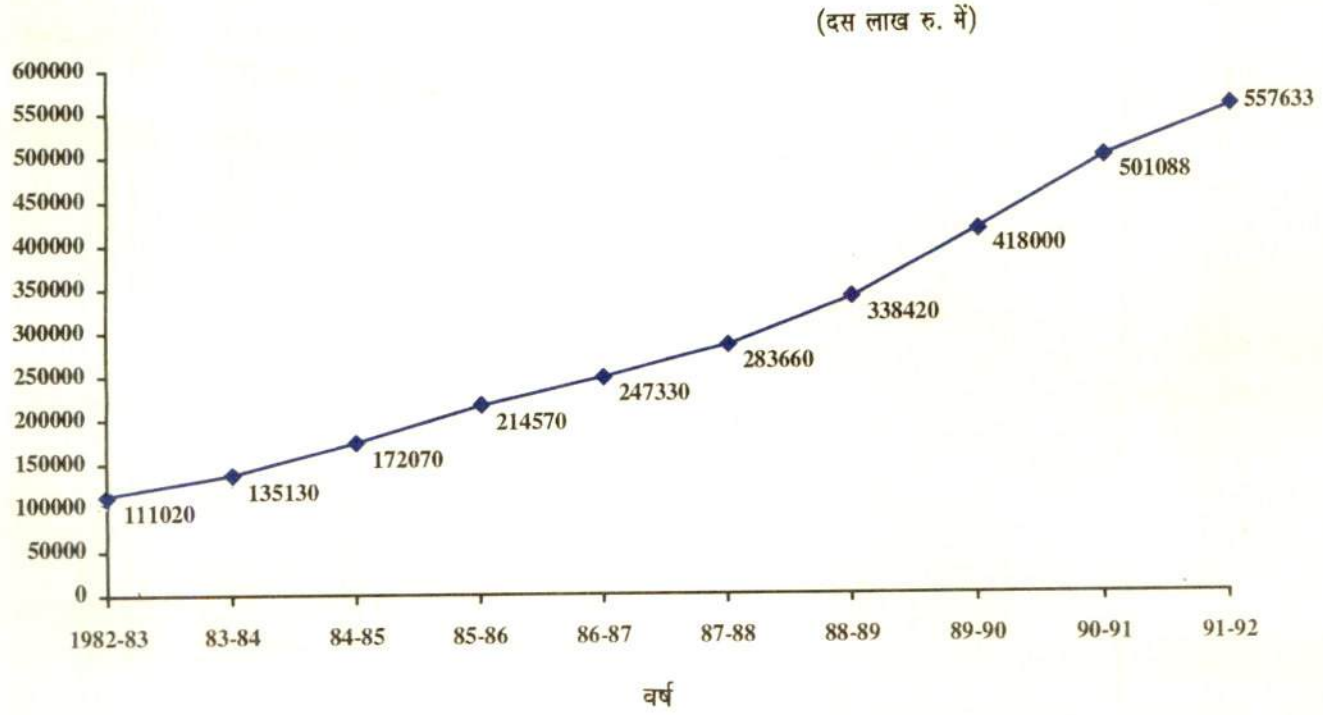

एजेन्सी सेवाएं

डाकघर बचत बैंक

डाकघर बचत बैंक, वित्त मंत्रालय की ओर से निम्नलिखित स्कीम चलाता है:-

बचत खाता

आवर्ती जमा खाता

सावधि जमा खाता

राष्ट्रीय बचत खाता योजना

मासिक आय खाता योजना

लोक भविष्य निधि

इन्दिरा विकास पत्र

किसान विकास पत्र

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आठवां निर्गम

दिल्ली के प्रधान डाकघरों में बचत बैंक कम्प्यूटरीकरण योजना आरंभ की गई है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के महत्वपूर्ण शहरों के चुनिन्दा प्रधान डाकघरों में योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा द्वारा निम्नलिखित चार प्रकार की पालिसियां प्रदान की जाती हैं:-

- आजीवन बीमा
- परिवर्तित आजीवन बीमा
- बंदोबस्ती बीमा
- प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा 15 वर्ष और 20 वर्ष

पिछले वर्ष 16, 91, 754 पालिसियों पर 2567.85 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया, जबकि वर्ष 1991-92 में यह बढ़कर 18,04,307 पालिसियों पर 3092.34 करोड़ रुपए हो गया । 31.3.92 की स्थिति के अनुसार गुजरात सर्किल में सबसे अधिक 2,68,559 पालिसियां थीं । वर्ष 1991-92 में 1,59,959 पालिसियों द्वारा 558.48 करोड़ रुपए का नया कारोबार किया गया, जो पिछले वर्ष के 1,56,358 पालिसियों के 476.27 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक है। गुजरात और कर्नाटक सर्किल ने क्रमशः 115.68 करोड़ रुपए और 55.60 करोड़ रुपए के नए कारोबार की वृद्धि की ।

बीमाकृत राशि की अधिकतम सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई।

(ग्राफ पृष्ठ 14 और 15 पर देखें)

कुल पालिसियों की संख्या

(दस लाख में)

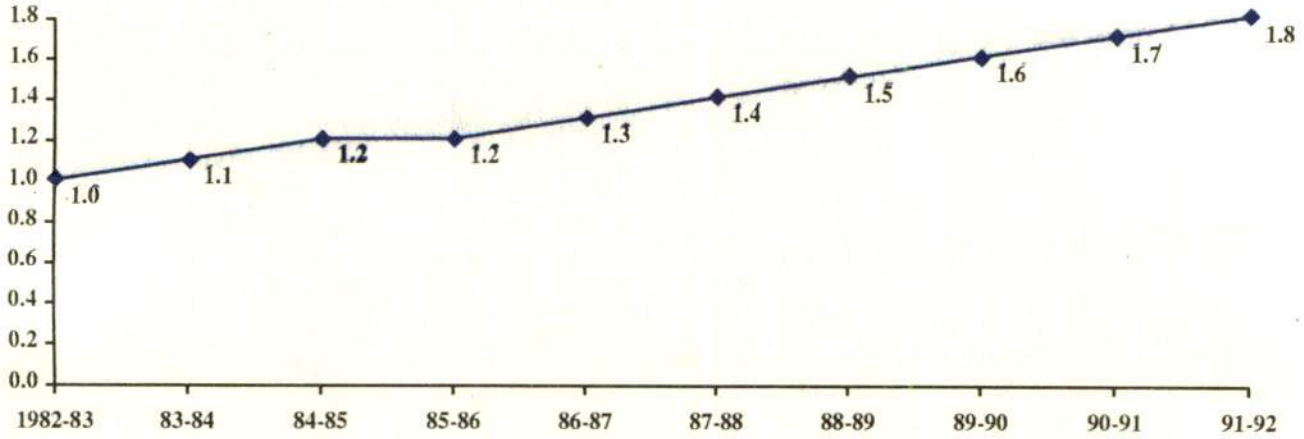

वर्ष

कुल बीमाकृत राशि

(दस लाख रु. में)

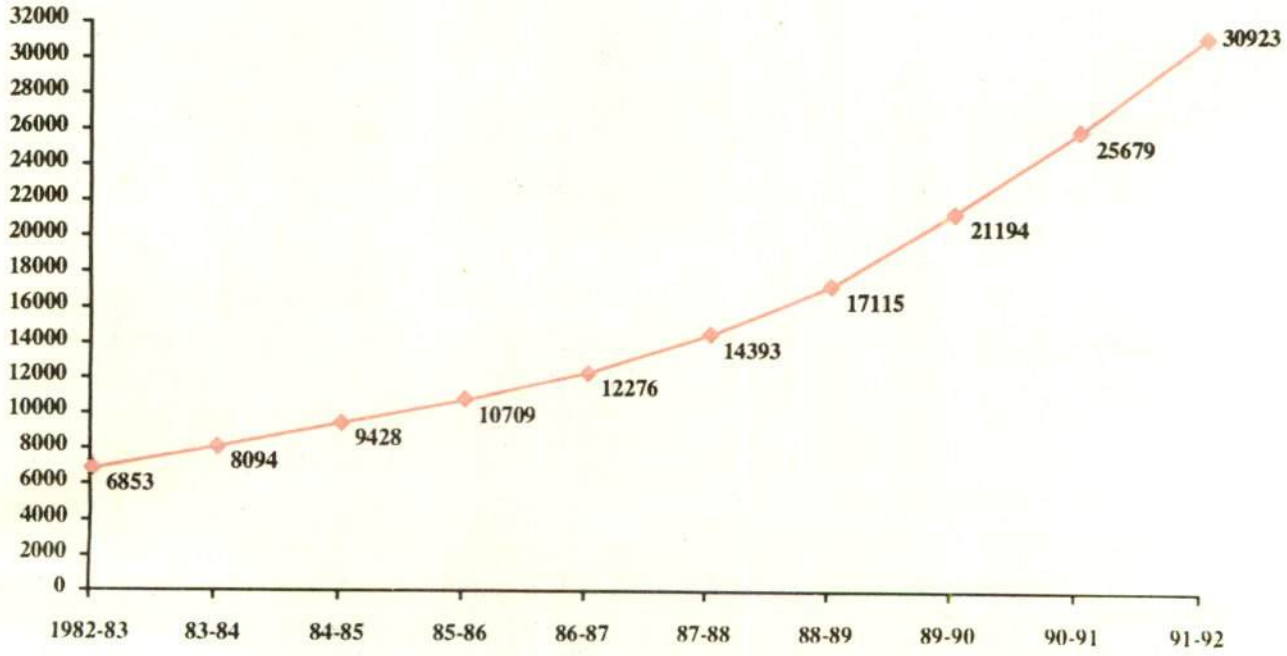

वर्ष

जीवन बीमा निधि

(दस लाख रु. में)

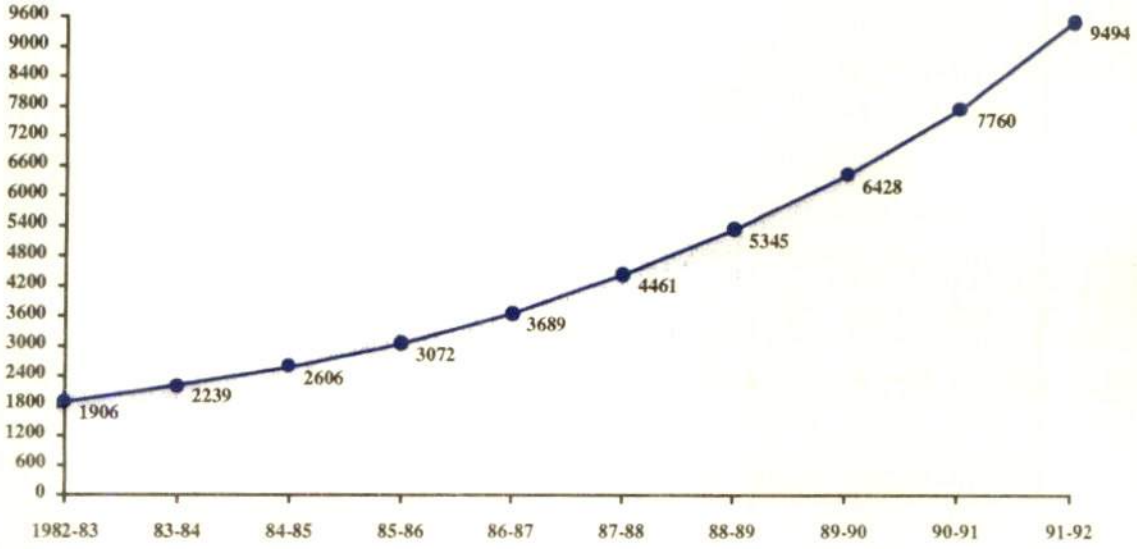

ग्राहक की संतुष्टि

वर्ष के दौरान 669950 जन शिकायतें प्राप्त हुई और पिछले वर्ष में प्राप्त हुई 682599 शिकायतों की जांच की गई । शिकायतों की दर कुल परियात का 0.00484% थी, जबकि पिछले वर्ष की दर 0.00461% थी ।

विपणन और वाणिज्यिक प्रचार

डाक विभाग ने ग्राहक संतुष्टि के लिए बाज़ार उन्मुखी मार्ग अपनाया है । ग्राहकों की आवश्यकताएं निर्धारित करने और उन्हें अपेक्षित सेवाएं प्रदान करके संतुष्ट करने का प्रयास करने, पहले से मौजूदा सेवाओं और उपलब्ध कराई जाने वाली नई सेवाओं का प्रचार करने के लिए डाक महानिदेशालय में मार्केटिंग डिवीजन स्थापित किया गया है । जनता और हमारे कर्मचारियों की नजर में विभाग की छवि उजागर करने के लिए कार्पोरेट आइडेंटिटी योजना आरंभ की गई है।

विभाग ने अपनी वाणिज्यिक प्रचार स्कीम के माध्यम से 1.30 करोड़ रुपए के विज्ञापन प्राप्त किए । अतः इस स्कीम से वर्ष 1990-91 में अर्जित राजस्व की तुलना में 73 लाख रुपए की वृद्धि हुई ।

पुनःप्रेषण पत्र

वर्ष 1991-92 के दौरान विभाग के 15 पुनः प्रेषण कार्यालयों द्वारा जो गैर-वितरित डाक का हिसाब रखते हैं, 31.2 मिलियन पत्रों का निपटान किया गया; उनमें से 57% पत्रों के पतों में सुधार करके उन्हें पाने वाले तक पहुंचाया गया और 26% पत्रों को उनका पता सुनिश्चित करने के बाद भेजने वाले के पास भेज दिया गया ।

डाक परिसर

विभाग ने वर्ष 1991-92 के दौरान भवन निर्माण संबंधी गतिविधियों पर 29.89 करोड़ रुपए की राशि खर्च की । इस रकम में से 27.72 करोड़ रुपए कार्यालय भवनों के निर्माण पर और 2.17 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए ।

वर्ष 1991-92 के दौरान, विभाग ने 82 कार्यालय भवनों, 203 स्टाफ क्वार्टरों और एक निरीक्षण क्वार्टर का निर्माण कार्य सम्पन्न किया तथा 82 कार्यालय भवनों, 169 स्टाफ क्वार्टरों और 2 निरीक्षण क्वार्टरों का नई परियोजनाओं के रूप में निर्माण कार्य आरंभ किया ।

डाक वित्त

वर्ष 1991-92 का कुल राजस्व 947.87 करोड़ रुपए था, जोकि पिछले वर्ष के 840.85 करोड़ रुपए की तुलना में 107.02 करोड़ रुपए (लगभग 12.7%) अधिक था। यह वृद्धि मुख्य रूप से बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंध तथा आंशिक रूप से 1 नवम्बर, 1991 से प्रभावी विदेश डाक प्रभार के शुल्क में वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 1991-92 का कुल कार्यकारी-व्यय 1162.15 करोड़ रुपये था, जोकि 1991-92 के संशोधित प्राक्कलन में दर्शाये गए अनुमानित व्यय 1175.00 की तुलना में 12.85 करोड़ रुपए कम था और दूसरा मुख्य कारण आर्थिक मानदंडों का सख्ती के साथ कार्यान्वयन था। तथापि, यह 1990-91 के वास्तविक व्यय 1032.50 करोड़ रुपये की तुलना में 129.65 करोड़ रु. अधिक था। यह वृद्धि 1.4.86 से पूर्व प्रभावी संशोधित दरों के परिणामस्वरूप और यह भी मुख्यतः रेलवे को बकाया ढुलाई-खर्च के भुगतान से हुई। भारत सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते की किश्तों की उच्चतर दरों तथा सामान्य मूल्यवृद्धि से व्यय पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

वर्ष 1991-92 का डाक-सेवाओं का राजस्व-घाटा 1990-91 के 191.65 करोड़ रुपए तथा 255 करोड़ रुपए (संशोधित प्राक्कलन 1991-92) की तुलना में 214.28 करोड़ रुपए था।

राजस्व तथा व्यय 1991-92
(वर्ष 1990-91 की तुलना में)

(करोड़ रुपए में)

ब्यौरे	1990-91	1991-92	पिछले वर्ष में परिवर्तित प्रतिशत
राजस्व			
डाक-टिकटों की बिक्री	511.66	569.91	11.38
नकद वसूल किया गया डाक शुल्क	173.18	201.31	16.24
मनीआर्डर और भारतीय पोस्टल आर्डर से प्राप्त कमीशन	110.46	126.11	14.16
अन्य प्राप्तियाँ	45.55	50.54	10.95
कुल	**840.85**	**947.87**	**12.72**
व्यय			
सामान्य प्रशासन	83.28	90.79	9.01
प्रचालन	905.49	1042.76	15.16
एजेंसी सेवाएं	46.31	54.84	18.42
अन्य	273.18	318.36	16.54
कुल सकल व्यय	1308.26	1506.75	15.17
वसूलियाँ घटाकर	275.76	344.60	24.96
निवल व्यय	**1032.50**	**1162.15**	**12.56**

महत्वपूर्ण वर्गों का सकल व्यय निम्न प्रकार से है :

वेतन एवं भत्ता, आकस्मिक व्यय और अन्य मदें	1004.60	1104.57	9.95
पेंशन संबंधी प्रभार	150.31	182.28	21.26
लेखा एवं लेखा-परीक्षा	30.88	33.30	7.83
डाक-टिकट तथा पोस्टकार्ड आदि	34.77	38.81	11.61
लेखन सामग्री एवं मुद्रण आदि	23.41	27.38	16.95
परिसंपत्ति इत्यादि का रखरखाव	1.49	7.35	393.28
मूल्यह्रास	5.40	6.00	11.11
छुटपुट कार्य	1.48	1.68	13.51
डाक की ढुलाई (रेलवे तथा एयर मेल कैरियर का भुगतान)	55.92	105.38	88.45
कुल	**1308.26**	**1506.75**	**15.17**

पोस्टकार्ड

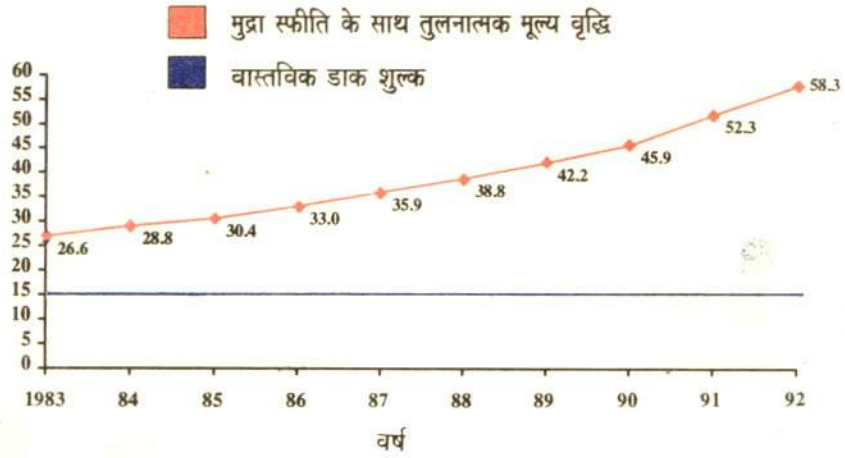

पत्र

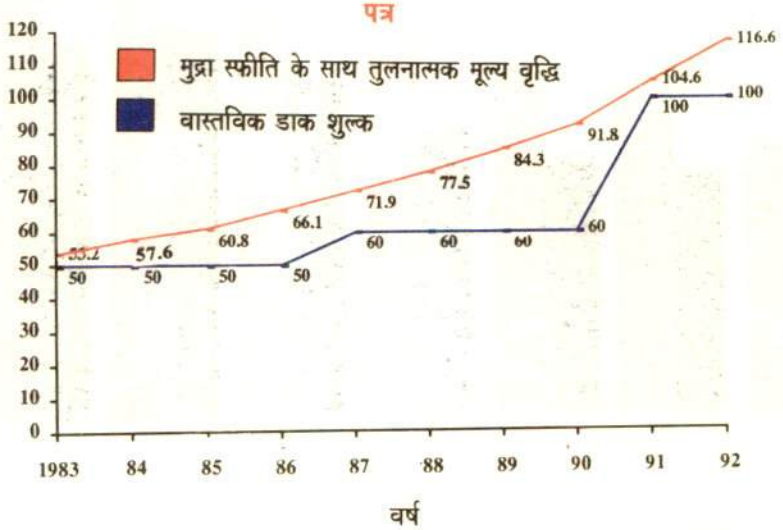

मानव संसाधन

मानव शक्ति

इस विभाग के कार्मिक ही भारतीय डाक प्रणाली के सबसे मुख्य संसाधन रहे हैं । 31.3.92 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 5.96 लाख थी, इनमें 3.05 लाख अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं, जिनका बहुत बड़ा भाग गांवों में डाक सेवाएं प्रदान करता है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभाग के प्रशिक्षण-संस्थानों में (क) पोस्टल स्टाफ कॉलेज, भारत, गाजियाबाद तथा (ख) सहारनपुर, मैसूर, वड़ोदरा, दरभंगा तथा मदुरै में स्थित डाक-प्रशिक्षण केन्द्र हैं ।

पोस्टल स्टाफ कॉलेज, भारतीय डाक सेवा और भारतीय डाक-तार वित्त एवं लेखा सेवा के सीधी भर्ती द्वारा आए अधिकारियों को प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करता है । इसके अलावा यह प्रबंधकीय/ कार्यकारिणी विकास कार्यक्रमों तथा पोस्टल एग्जीक्यूटिव्ज के लिए विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन करता है । यह द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत या यू.एन.डी.पी./यू.पी.यू. आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की प्रायोजकता के अंतर्गत विदेश डाक प्रशासन के अधिकारियों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करता है । 1991-92 के दौरान इसने 15 प्रवेश तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया । इनमें "डाक पारेषण", "डाक संपदा प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम" तथा "जनसंपर्क तथा विपणन का प्रबंध-समालोचना पाठ्यक्रम" पर आयोजित कार्यशालायें भी शामिल हैं । अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए दो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए (क) पहला "वरिष्ठ डाक प्रबंध" पर यू. पी. यू. द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम था जो 18.11.91 से 14.12.91 तक आयोजित किया गया और जिसमें 13 देशों के 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया (ख) "ग्राहक की देख-रेख" पर 4.3.92 से 10.3.92 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 6 सार्क देशों के 8 प्रतिभागियों ने भाग लिया । पोस्टल स्टाफ कॉलेज, भारत, गाजियाबाद ने हरे-भरे तथा प्रदूषणमुक्त वातावरण के निर्माण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसर में एक व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी अपनाया।

डाक प्रशिक्षण केन्द्र (पी.टी.सी.) निरीक्षकों /पर्यवेक्षकों/डाक सहायकों/ छंटाई सहायकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबंध करता है । इन प्रशिक्षण केन्द्रों में उन कर्मचारियों के लिए भी प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो उच्चतर प्रबंधकीय स्तर के पदों पर पदोन्नत हो गए हैं ।

वर्ष 1991-92 के दौरान डाक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कुल 14206 पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जब संभव होता है प्रशिक्षण हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में देने का ध्यान रखा जाता है ।

द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा

यह स्मरणीय है कि विभाग ने वर्ष 1983 में अपने मूल प्रचालनात्मक संवर्गों में समयबद्ध एक पदोन्नति योजना शुरु की थी। द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा द्वारा समूह "ग" और समूह "घ" के प्रचालन संवर्गों में सभी कर्मचारियों के सेवाकाल में बढ़े हुए कार्य संतोष और अधिक उत्पादकता के दोहरे उद्देश्य को लेकर दूसरी समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करने की योजना तैयार की गई और इस वर्ष कार्यान्वित की गई । इस योजना में समूह "ग" के लगभग 35,000 और समूह "घ" के लगभग 9,000 कर्मचारी शामिल हैं ।

समयबद्ध एक पदोन्नति योजना का लाभ, अ.श्रे.लि./उ.श्रे.लि. संवर्गों के डाक सहायकों, एस.बी.सी.ओ. में परिवर्तित हो जाने के द्वारा एस.बी.सी.ओ. स्टाफ को भी प्रदान किया गया।

स्टाफ संबंध

विभाग अपने स्टाफ की समझदारी और सहभागिता का सम्मान करता है और उनके प्रबंध-ज्ञान तथा इसकी नीतियों का समर्थन करता है । इस प्रकार के संबंध विभाग के विकास से संबंधित हमारी योजनाओं और विभाग के मानव संसाधनों की समृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण हैं । विभाग अपनी मौजूदा समस्याओं और भविष्य की कार्य योजनाओं की रूपरेखा के बारे में परामर्श और पुनरीक्षा के लिए कर्मचारी यूनियनों की तीन फेडरेशनों तथा उनके घटकों और फेडरेशनों से असम्बद्ध यूनियनों और एसोसिएशनों को भी शामिल करता रहा है।

विभाग का तीन फेडरेशनों तथा कर्मचारियों और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की 27 यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ अर्थपूर्ण संबंध हैं। डाक विभागीय परिषद् (जे.सी.एम.) की दो बैठकों के अलावा इसकी स्थायी समिति की 11 बैठकें हुईं । अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए एक नई विभागीय समिति का गठन किया गया और इसकी पहली बैठक जनवरी, 1992 में हुई ।

अनुसूचित जाति/जनजाति

विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए नियुक्तियों/पदोन्नतियों में आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के

आदेशों में दिए गए सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार सख्ती से लागू किया जाता है ।

क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्पर्क अधिकारियों तथा मंत्रालय के संपर्क अधिकारी द्वारा आरक्षण समाप्त करने से संबंधित सभी प्रस्तावों की छानबीन इस बात पर यथोचित ध्यान देते हुए की जाती है कि संबंधित सरकारी आदेशों का पूरी तरह पालन हो । प्रशासनिक शाखाओं/कार्यालयों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों को तत्काल दूर करने के लिए वरीयता दी जाती है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान 67 अभ्यावेदन/व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त हुई तथा इनमें से 57 मामलों का निपटान कर दिया गया।

आंतरिक कार्य-अध्ययन

"स्पीड पोस्ट" में एस. आर. एम., ए.एस.पी./ए.एस. आर. एम. /इंस्पेक्टरों, एल. एस. जी. सुपरवाइज़रों और डाकियों के पद मंजूर/सृजित करने के लिए मानदण्ड बनाने का अध्ययन कार्य पूरा किया गया और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

— मेल मोटर यूनिटों में लिपिकीय स्टाफ की मंजूरी से संबंधित मानदण्ड तैयार करने का अध्ययन पूरा किया गया।

— एस.सी.टी. सेल, सी डब्ल्यू (पी) अनुभाग, डी.सी. अनुभाग, इंस्पेक्शन तथा ओ एंड एम अनुभाग का कार्य अध्ययन किया गया ।

— डाक लेखा कार्यालय के मनीआर्डर अनुभागों में डेबिट चेकर्स/सार्टरों के मानदण्डों अर्थात् उत्पादकता दर की पुनरीक्षा का कार्य अध्ययन पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

— डाकघरों में राष्ट्रीय बचत पत्रों को निपटाने से संबंधित मानदण्डों के पुनरीक्षण का कार्य अध्ययन किया गया।

— निदेशालय के जाँच अनुभाग, सी.आर. अनुभाग तथा पी.एफ. अनुभाग का कार्य अध्ययन किया गया ।

— निदेशक, डाक लेखा, मद्रास के कार्यालय में डाटा प्रोसेसिंग सहायकों की आवश्यकता का कार्य अध्ययन ।

उत्कृष्ट कार्य को मान्यता

विभाग उन कर्मचारियों को मेघदूत पुरस्कारों से सम्मानित कर, यथोचित मान्यता प्रदान करता है जिनकी सेवाएं सराहनीय होती हैं ।

विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए "मेघदूत" पुरस्कार प्रदान किए :

1. श्री मोहन लाल, अतिरिक्त विभागीय रनर, पंजाब
2. श्री कृष्ण लाल -II, इन्स्पेक्टर, रेल डाक सेवा, पंजाब
3. श्री यू.ए. पठान, ड्राइवर, गुजरात
4. श्रीमती गंधर्ववती, डाक सहायक , हिमाचल प्रदेश
5. श्रीमती किरण गर्ग, डाक सहायक, दिल्ली ।

कर्मचारी कल्याण

डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड संचार मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता रहा । बोर्ड का उद्देश्य इस विभाग के कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं एवं कल्याण, खेल-कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित, विकसित करना, उनका आयोजन तथा उन पर नियंत्रण रखना है । इस प्रयोजन के लिए बोर्ड को सरकार से सहायता अनुदान मिलता है । इसके अतिरिक्त स्टाफ द्वारा स्वैच्छिक अंशदान अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा भी धन एकत्र किया जाता है ।

कल्याण बोर्ड के धन का खेलों, कम्युनिटी सेंटर, मनोरंजन कल्बों आदि गतिविधियों के लिए, बीमारी, मृत्यु तथा प्राकृतिक विपदाओं में वित्तीय सहायता देने, शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना, भ्रमण के लिए आर्थिक सहायता, विकलांग कर्मचारियों एवं उनके बच्चों को सहायता अनुदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, शिशु गृहों आदि जैसे कार्यकलापों के लिए इस्तेमाल किया जाता है । वर्ष 1991-92 के दौरान कल्याण कार्यकलापों पर 90 लाख रुपये खर्च किए गए । उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में भूकम्प से प्रभावित कर्मचारियों को विशेष राहत प्रदान की गई । अन्य सर्किलों के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक दान और सर्किल कल्याण निधि से दिए गए अनुदान के अतिरिक्त कल्याण निधि से 8 लाख रुपये का अनुदान दिया गया ।

स्कूली छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और पुरस्कार की दरों में वृद्धि की गई । शिशु गृहों, सिलाई केन्द्रों, आवासीय कल्याण एसोसिएशनों इत्यादि को दिया जाने वाला सहायता अनुदान भी बढ़ाया गया । कल्याण निधि की सहायता से चौदह शिशु गृह और 25 सिलाई केन्द्र चल रहे हैं । केन्द्रीय डाक महिला संगठन तथा उसके तदनुरूप सर्किलों में महिला संगठन, महिला कर्मचारियों और उनके आश्रितों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं । ये संगठन शिशु गृह, सिलाई केन्द्र, नृत्य एवं संगीत कक्षाएं चला रहे हैं । क्षेत्रीय डाक महिला संगठन के तत्त्वावधान में कानपुर में, कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रारम्भ किए गए अध्ययन कक्ष एवं लाइब्रेरी ने कल्याण कार्यकलापों को एक नई दिशा प्रदान की है।

अवकाश गृह

कर्मचारियों और उनके परिवार के हित के लिए 19 अवकाश गृह हैं ।

खेल

वर्ष के दौरान वॉलीबाल, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, एक्वैटिक, एथलैटिक, साइक्लिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती, शतरंज, हॉकी और बास्केटबाल जैसे खेलों के लिए अखिल भारतीय डाक सेवा टूर्नामेंट आयोजित किए गए। फरवरी, 1992 में नागपुर में अखिल भारतीय डाक सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभाग के अनेक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल-प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लिया।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

विभाग अपने मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा के रूप में हिन्दी का अधिक-से-अधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय और सभी सर्किल मुख्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई।

प्रोत्साहन और सद्भावना के माध्यम से हिन्दी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने की नीति को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। इन योजनाओं में:

1. अखिल भारतीय डाक राजभाषा शील्ड,
2. डाक विभाग मौलिक हिन्दी पुस्तक पुरस्कार योजना,
3. "डाक पत्रिका" में हिन्दी में मूल लेख लिखने के लिए पुरस्कार,
4. डाक विभाग राजभाषा शील्ड,
5. हिन्दी में मूल नोटिंग और ड्राफ्टिंग के लिए प्रोत्साहन,
6. निबन्ध प्रतियोगिता,
7. हिन्दी वॉक् प्रतियोगिता; और,
8. हिन्दी प्रश्न मंच शामिल हैं।

भाग - 2

वार्षिक रिपोर्ट

1992-93

डाक नेटवर्क का विस्तार

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक नेटवर्क का विस्तार कार्य जारी रहा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण डाकघर बिना विलम्ब किए खोले जायें, सरकार ने अतिरिक्त विभागीय डाकघर खोलने से संबंधित शक्तियां सर्किल कार्यालयों को सौंप दीं । इन शक्तियों को उक्त कार्यालयों को सौंप दिए जाने से तुरन्त कार्रवाई करने में सहायता मिली और फरवरी, 93 तक 452 डाकघरों को मंजूरी दी गई । यह सुनिश्चित किया गया कि डाकघर योजना लक्ष्यों और सरकार के मानदंडों के अनुसार खोले जाएं ।

स्पीड पोस्ट

स्पीड पोस्ट सेवा की दर संरचना, समुचित प्रचार और विपणन तकनीकों को युक्तिसंगत बना कर उसे और अधिक सुदृढ़ बनाया गया । हावड़ा (पश्चिम बंगाल में) 1 जून, 1992 से स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ की गई । 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार देश भर में प्वाइंट टू प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा के तहत 317 युग्म स्टेशन कार्य कर रहे थे । 1 दिसम्बर, 1992 से घाना, हंगरी, मलेशिया, मोरक्को, यूगांडा, गुयाना, डेनमार्क, ईरान, मैक्सिको, नाइजर, पनामा, पपुआ, न्यू गिनी, जायरे के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट संपर्क स्थापित किए गए ।

प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन

मनीआर्डरों के शीघ्र प्रेषण के लिए विभाग ने उपग्रह के माध्यम से मनीआर्डर प्रेषण की एक परियोजना तैयार की जिससे अन्ततः मनीआर्डरों का शीघ्र भुगतान हो सकेगा । इस प्रयोजन के लिए 75 माइक्रो अर्थ स्टेशन (वी.एस.ए.टी.) स्थापित करने के इस परियोजना के प्रथम चरण को सरकार ने मंजूरी दे दी है । डाक मदों पर मोहर की छाप में सुधार लाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली डाक-टिकट विरूपण मशीनें और मशीनों से बनी हाथ की मोहरें प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की गई है।

पासपोर्ट आवेदन फार्मों की बिक्री

डाक विभाग और विदेश मंत्रालय ने मिलकर दिनांक 1 नवम्बर, 1992 से देश के सभी 834 प्रधान डाकघरों और अन्य 1038 उप डाकघरों में पासपोर्ट आवेदन फार्मों की बिक्री प्रारंभ की है । यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि आवेदन फार्म आसानी से उपलब्ध हो सकें । जनवरी, 1993 से पासपोर्ट कार्यालय और डाकघर ही पासपोर्ट आवेदन फार्मों की बिक्री के एकमात्र केन्द्र होंगे।

डाकघर के अवकाश के दिन डाक वितरण की शुरूआत

वर्ष 1982 तक पूरा शुल्क अदा की गई अपंजीकृत डाक का डाकघर के अवकाश के दिन वितरण किया जाता था । लेकिन, उसी वर्ष इसे बंद कर दिया गया । इन वर्षों के अनुभव से यह पता चला कि कभी-कभी अवकाश लगातार पड़ जाते हैं अथवा रविवार से पहले दिन या बाद वाले दिन पड़ते हैं जिससे लगातार एक से अधिक दिनों तक डाक का वितरण नहीं हो पाता है । इससे जनता को काफी असुविधा होती है । इस समस्या पर काबू पाने के लिए अक्तूबर, 92 से चुने गए अवकाश के दिनों को पूरा शुल्क अदा की गई अपंजीकृत डाक का वितरण शुरु किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लगातार अवकाश के दो दिन, जिनमें रविवार भी शामिल है, डाक वितरण के बिना न छूट सकें तथापि, 3 राष्ट्रीय अवकाशों अर्थात् गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयन्ती तथा रविवार के दिन डाक का वितरण नहीं होगा ।

मूल्यदेय डाक मदों की मूल्य सीमा

मूल्यदेय डाक मदों की मूल्य-सीमा को दिनांक 30.6.1992 से 1000 रु. से बढ़ाकर 2000 रु. कर दिया गया ।

सेना डाकघरों द्वारा मनीआर्डर का भुगतान

लगभग 500 सेना डाकघर पूर्ण रूप से सैन्य बलों को सेवा प्रदान कर रहे हैं । अब तक सेना डाकघर मनीआर्डर बुक कर रहे थे, परन्तु उनका भुगतान नहीं कर रहे थे, अब यह निर्णय लिया गया है कि सेना डाकघर अन्य डाकघरों की तरह मनीआर्डरों का भुगतान भी करेंगे ।

विश्व डाक संघ से संबंध

भूटान के डाक प्रशासन के अनुरोध पर डाक विभाग ने भूटान के 15 कर्मचारियों के लिए एक डाक -तार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया । यह पाठ्यक्रम दिनांक 1.12.92 से डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम की अवधि लगभग 8 माह है। विभाग ने यू.पी.यू. की एक स्कीम के तहत अल्प विकसित देशों को तकनीकी सहयोग के अंतर्गत छः फैलोशिप प्रदान करने का निर्णय किया है । इस कार्यक्रम के तहत फिलैटली, ई.एम.एस. मेल मॉनीटरिंग जैसे क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है ।

विश्व डाक संघ की डाक अध्ययन सलाहकार परिषद् (सी.सी.पी.एस.) का वार्षिक अधिवेशन 12 अक्तूबर से 23 अक्तूबर, 1992 तक बर्न (स्विट्जरलैंड) में सम्पन्न हुआ । श्री एल.डी.बोनेल तत्कालीन सचिव (डाक) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने इस वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। इस प्रतिनिधि मंडल में श्री एस.के पार्थसारथी, तत्कालीन सदस्य (कार्मिक) और अब सचिव, डाक विभाग तथा उप- महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) शामिल थे। डाक अध्ययन सलाहकार परिषद् (सी.सी.पी.एस.) के इस अधिवेशन में मानव संसाधन, अनुसंधान और विकास, ई.एम.एस. और पोस्टल मार्केट पर हुई चार संगोष्ठियां अधिवेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं।

फिलैटली

नए रंग की डाक स्टेशनरी की शुरुआत की गई । नीले शेड वाले नियमित अंतर्देशीय पत्र कार्डों के अतिरिक्त इस वर्ष हल्के गुलाबी रंग तथा हल्के स्लेटी रंग के अंतर्देशीय पत्र कार्ड शुरु किए गए । इस वर्ष हल्के समुद्री हरे रंग तथा हल्के नीले रंग के पोस्टकार्ड प्रारंभ किए गए ।

1.4.92 से 31.12.92 की अवधि के दौरान राज्य स्तर की दो फिलैटलिक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं । एक प्रदर्शनी कर्नापेक्स में 11.9.92 से 13.9.92 तक कर्नाटक सर्किल द्वारा मैसूर में और दूसरी राजपेक्स राजस्थान सर्किल द्वारा जयपुर में 20.11.92 से 23.11.92 तक आयोजित की गई थी ।

विभाग ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय फिलैटलिक प्रदर्शनियों में भाग लिया जिनमें भारतीय डाक-टिकट प्रदर्शित किए गए व बेचे भी गए:

- ग्रेनेडा में 24.4.92 से 3.5.92 तक आयोजित ग्रेनेडा-92
- शिकागो में 22.5.92 से 31.5.92 तक आयोजित एक्सपो- 92; और
- कुआलालम्पुर में 1.9.92 से 7.9.92 तक आयोजित कुआलालम्पुर-92 ।

1.1.93 से 31.3.93 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित राज्य स्तरीय प्रदर्शनियां आयोजित करने का प्रस्ताव है:-

- अर्णाकुलम में 16.1.93 से 20.1.93 तक कैरपैक्स-93; और
- रायपुर में 4.2.93 से 6.2.93 तक मपैक्स-93

मेघदूत पुरस्कार

निम्नलिखित कर्मचारियों को मेघदूत पुरस्कार के लिए चुना गया:

- श्री रघुवीर सिंह, अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर, हरियाणा सर्किल,
- श्री एम.जी. रमन्ना, पोस्टमैन, कर्नाटक सर्किल
- श्री आर.के.सक्सेना, डाक सहायक, उत्तर प्रदेश सर्किल
- श्री आर रविन्द्रन पिल्लै, सहायक अधीक्षक डाकघर, केरल सर्किल; और
- श्री ध्यान सिंह, मेलगार्ड पंजाब सर्किल

सर्किल अध्यक्षों का सम्मेलन

सर्किल अध्यक्षों का सम्मेलन 29 तथा 30 जुलाई, 1992 को सम्पन्न हुआ । इस सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श हुआ तथा नीति निर्णय लिए गए । ये निर्णय विभाग की भविष्य की कार्य-प्रणाली के लिए आधार तैयार करेंगे ।

राजभाषा

डाक निदेशालय में दो हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । हिन्दी के प्रति जागरूकता लाने तथा राजभाषा के रूप में इसके प्रगामी प्रयोग के लिए डाक निदेशालय में 14 सितम्बर से 18 सितम्बर, 1992 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । इस सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे हिन्दी नोटिंग और ड्राफ्टिंग, हिन्दी वाक् प्रतियो- गिता, हिन्दी निबंध, हिन्दी प्रश्न मंच, हिन्दी स्टेनोग्राफी, टाइपिंग प्रतियोगिता इत्यादि । इन प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान पाने वालों को पुरस्कृत किया गया । विभाग के सर्किल/क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपर्युक्त अवधि के दौरान हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन किया गया।

इस अवधि के दौरान निदेशालय के राजभाषा अनुभाग ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयोग के लिए अपनी तकनीकी शब्दावली और मानक मसौदे डिग्लाट रूप में तैयार किये ।

Part - 1
Annual Report
1991-92

OVERVIEW

The highlight of the year under review has been the stress on the modernisation of the Postal Services. In the last report, it was mentioned that after a period of comparative lull in the technology induction in the past years, definite objectives in the field of modernisation were drawn up in the year 1991-92. The Steering Group set up by the Minister of State for Communications for directing and supervising the programmes of technology induction, monitored the progress in this area and provided the necessary fillip to the existing and the projected schemes. Activity in the thrust areas identified for the modernisation of the Postal Services thus registered satisfactory progress during the year.

Post Office Computerisation

The use of programmed memory in micro-processors for calculation of postal tariff due on an article, depending on the weight and class of the postal article, helps in reducing the time needed for completing a counter transaction. The objective of providing multiple service transactions through a single window, can be achieved through the concept of a PC based multipurpose counter machine. Hardware and software was evolved for such machines through the Computer Maintenance Corporation of India (CMC) and Bradma India Ltd., and a beginning was made by installation of 102 machines in 22 selected post offices in major cities in 1991. The feedback on the performance of these machines revealed that besides reducing the waiting time at the counter and offering different kinds of services at a single window, an operator working on this machine is generally able to handle greater number of transactions than could be manually completed by two Counter Assistants during the same time-frame. Customer satisfaction has thus been an added positive factor in these machines. For 1992-93, orders have therefore, been placed on two public sector undertakings for supply of an additional 1000 computer - aided counter machines to various post offices. The Department proposes to instal at least 5000 such machines during the Eighth Five - Year Plan.

Progress of Savings Bank computerisation also has been satisfactory in the seven Head Post Offices of Delhi Circle. It will be recalled that the first SB computerisation scheme was implemented in Delhi in 1986. The Eighth Five-Year Plan envisages computerisation in at least 21 Head Post Offices in the country including upgradation of the system already provided in some of the Head Post Offices.

As regards the Postal Life Insurance, the existing systems in Karnataka, Maharashtra, Tamilnadu and Gujarat Circles are proposed to be upgraded to handle large number of PLI policies and transactions. The PLI operations in all the remaining Circles are proposed to be computerised by 1994. The gradual progress in computerisation in this way would lead to staff acculturation, optimum efficiency, improved motivation, and increased customer satisfaction.

It may be worthwhile to mention that all schemes for modernisation are implemented in consultation with the Unions.

Mechanised Sorting

A reference to the agreement signed between Department of Posts and Alcatel - Bell of Belgium, was made in the last report. Under this agreement, an Automatic Integrated Mail Processing System was to be installed at Bombay. The equipment consisting of two computerised letter sorting machines and 30 manual coding desks in six suites with control facilities has since been received at Bombay and is under installation. Acceptance testing is going on. The system is expected to be commissioned by March '93. The Eighth Five - Year Plan envisages installation of three systems. It is proposed to instal the next system at Madras during 1993-94.

Satellite Money Order Service

The Government has since approved a plan to instal 75 micro-earth stations (also called Very Small Aperture Terminals - VSATs) to transmit money order advices via satellite communications. The Department of Electronics will provide all the technical support necessary for implementing the project. The new technol-

ogy is expected to reduce the cost of money order operations. The network so developed will also help the Department to launch new value added services in the future, such as electronic money transer, GIRO, message transmission etc. These services have substantial potential to generate additional revenues for the Government.

Stamps, Seals and Postal Machines

High Speed Stamp Cancelling Machines, with capacity of dealing with 400 articles per minute, as well as low speed machines with a capacity for cancelling 150 articles per minute, are now operating in many of our post offices. After an initial experiment of successfully operating 60 such machines, the Department now proposes to supply another 270 machines to the post offices. The Department has also placed orders for manufacture of machine engraved steel hand stamps for cancellation. The Department has opened a dialogue with the Director General of Ordnance Factories and Hindustan Teleprinters Ltd., for the manufacture of hard steel engraved stamps. In respect of electronic franking machines, the Department has approved seven different models manufactured by different companies in this country. The approval of computerized models of franking machines is also being examined.

Expansion of Network

In the last report, mention was made of the introduction of new norms for opening post offices during the Eighth Five-Year Plan. In order to speed up the opening of post offices, the government has since delegated the powers to the Heads of Circles, to open the post offices which satisfy the norms. However, it is necessary to evaluate the expansion programme carried out so far with a view to assessing the impact of such post offices on rural development and to close down those which have been proving to be chronically uneconomical. The question of replacing the traditional system by a new system under which licensed agents who could handle the post business both in the rural and urban areas is separately engaging the attention of the Department.

Asian Pacific Postal Union (APPU)

The meeting of the Executive Council of the Asian Pacific Postal Union was held at New Delhi from 15th September, 1992 to 21st September, 1992. This meeting discussed major issues which confront the member countries of the APPU on account of the changed economic and commercial scenario of the world. The progress made by member countries towards implementation of the Washington General Action Plan was also reviewed. An important outcome of the conference was the New Delhi resolution which was unanimously passed in support of the integrity of the Universal Postal Union and emphasized the need to keep up the traditions of the UPU.

SAL Service

The introduciton of Surface Air Lifted (SAL) mail service is in keeping with the resolve of the Department of Posts to provide its customer a wider range of services to meet their growing needs and maximise their satisfaction. To begin with, it has been decided to introduce SAL service from India to four foreign destinations, namely, UK, USA, Germany and Singapore. The carrier of SAL mail will be by Air India which has offered 50% discount on freight and will accept payment in Indian currency. Air India will lift such mails once a week. The arrangement will make a qualitative difference in the transit time now taken by surface mail from India to the four foreign destinations which on an average worked out to two to three months before the introduction of SAL mail service. The new service will make it possible to transmit surface mails to these countries in approximately ten days' time. SAL Mail will continue to get the treatment of surface mail in the country of origin upto the office of exchange and in the country of destination from its office of exchange to the point of delivery, but will get air transmission between the two countries. The success of this experiment will lead to its extension to other countries.

Philately

The programme for issue of postage stamps, definitive as well as commemorative, continued through

this period with stamps on the golden jubilee of the Quit India Movement, the diamond jubilee of the Indian Air Force, and on endangered species of birds and many others, providing a happy mix of solemn and colourful themes. Efforts to improve the postal stationery led to the issue of Inland Letter Cards and Post Cards in different colours. The new colours were quite popular. Inland Letter Cards with an enlarged format which will be fully closed on all sides will also be produced very shortly to make them more suitable for machine - processing, thus marking the beginning of a new era in the history of the Post in India. Several other programmes are in hand for diversifying production of philatelic issues for greater customer-satisfaction.

Expenditure - Revenue Gap

In the year 1991-92, the net working expenditure of the Department was Rs.1162.15 crores against a revenue of Rs.947.87 crores. The gap thus being Rs.214.28 crores. While efforts have been made to control the expenditure, augmentation of revenue also has been ensured more through better management rather than by revision of tariff. Domestic tariff has not been revised since June, 1990 in spite of regular wage increase to our staff. However, certain changes were made in respect of Foreign Postage rates in the month of Nov. '91. The Department has placed emphasis on modernisation and structural improvements with a view to bringing down the deficit by improving the efficiency to optimum levels.

Eighth Five-Year Plan

The Eighth Five Year Plan of the Department has since been approved by the Government. The main emphasis of this Plan is the technological thrust which will be ensured through the continuation and extension of the various programmes initiated during the Seventh Plan. An outlay of Rs.325 crores has been approved by the government for the entire Plan period.

Future Scenario

In order to ensure that the Department is revitalised to meet the rapidly changing environment and also to take care of enhanced public expectations from the Postal Services, a Social Audit Panel headed by Shri Justice P.N. Bhagwati, former Chief Justice of India, consisting of Dr. N.K. Bhaskar Rao as Member - Convenor, Shri Khushwant Singh, Vice Admiral S. Chopra (Retd.), Air Marshal J.K. Seth (Retd.) and Shri B.G. Deshmukh, Cabinet Secretary (Retd.) as Members was constituted by the Minister of Communications in March 92. The Panel has held over 20 open - house sessions in metropolitan cities and other important towns to elicit the views of the public regarding the state of the Postal Services and to obtain suggestions and ideas for their improvement. The Panel has submitted report on various aspects relating to improvement in delivery of mails, extension of Speedpost network, modernisation agency functions and the structure and functions of the Postal Services Board. These reports are under examination with the Board.

The Indian Post Office Act which provides the statutory foundation for the Post Offices in India is almost 100 years old and the need for comprehensive changes in the Act has been felt from time to time. There has been substantial changes in the international postal system and the economic scenario of the country which need to be reflected in the Act. The Government, therefore, constituted a Committee headed by Shri Gurcharan Singh, a retired Member of the Postal Services Board with senior officers of various concerned Ministries as Members to examine the Indian Post Office Act, 1898 and to recommend necessary changes. The Committee has since finalised the deliberations and has submitted its report.

Future development of the postal services would take into account the recommendations of Social Audit Panel as well as the Committee constituted for the revision of the Indian Post Office Act. The Department of Posts is poised to meet the challenges of the modern Indian socio-economic environment with spirit of its tradition of efficient, self-less service to the people.

ORGANISATION

The Department of Posts was created in January, 1985 after the bifurcation of the erstwhile Posts and Telegraphs Department. It is a part of the Ministry of Communications. The Ministry functioned under the charge of Shri Rajesh Pilot, Minister of State for Communications, with Shri P.V. Rangayya Naidu, as the Deputy Minister for Communications during the period under review. Shri Sukh Ram took over as Minister of State for Communications on 18th January, 1993.

Headquarters

The management of the Department vests in the Postal Services Board which has a Chairman and three Members. The Secretary, Department of Posts is the Chairman of the Board. He is also the Director General, Posts. The Members hold the portfolios of Operations, Development and Personnel. In addition, there is a Financial Adviser. The Board is assisted by a Secretary, Postal Services Board. The Board directs and supervises the management of the Postal Services in the country with the assistance of sixteen Deputy Directors General in the Directorate General of Posts.

Circles

The Department's operational responsibilities are borne by the 19 Circles into which the country is divided. A circle comprises one or more States/Union Territories and is headed by a Chief Postmaster General and is generally divided into Regions composed of a group of Postal Divisions. Each Region has a Postmaster General for providing high level management support to the Chief Postmaster General in the field. In addition to the Circles, there are Regional Mail Planning Units at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras under Controllers who are of the rank of a Postmaster General. The Controllers bring exclusive professionalism to the function of mail operations. There are also other functional Divisions and Units like Mails Division, Stores Depot, Stamp Depot and Mail Motor Service, in a Circle.

Indian Post Offices are categorised as Head, Sub and Branch Post Offices. Branch Post Offices are mostly Extra Departmental Post Offices located in rural areas. The Sub Post Offices, mostly, are Departmental Post Offices. Head Post Offices are graded into five categories according to their size, the biggest being the General Post Offices of Bombay and Calcutta, followed by the GPO's at Madras, Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Kanpur, Lucknow and other major cities of the country.

The Army Postal Service is headed by a Major General. He is designated as Additional Director General, APS and is also described as Chief Postmaster General, APS circle.

Positions

On 31st March, 1992, the Postal Services Board consisted of Shri S.P. Ghulati, Secretary (Posts), Director General , Posts, and Chairman, Postal Services Board, Shri S.K.N. Nair, Member (Finance) Telecom. Commission who looked after the work of Member (Finance) in the Postal Services Board, and Shri L.D. Bonnell as Member (Personnel). With the retirement of Shri S.P. Ghulati, Shri L.D. Bonnell, took over as Secretary (Posts) on 1.6.92 and held the post till his retirement on 31.10.92. Shri S.K. Parthasarathy who functioned as Member (Personnel) from 11.6.92 took over as Secretary (Posts) on 31.10.92 and continues as such. Currently, Shri M.S. Raghavan is the Member (Personnel), Shri T.E. Raman, is Member (Operations) and Shri S.R. Faruqi is Member (Development) in the Board. Shri Y.L. Rajwade is the Secretary, Postal Services Board. Shri G.S. Rajamani is the Financial Adviser, Dept. of Posts, and is a permanent invitee to the Board.

International Postal Relations

India continued to play a leading role in International Postal Af-

fairs as a member of Universal Postal Union (UPU) and of the Asian Pacific Postal Union (APPU). In both these organisations India holds certain important positions -namely Chairman of Committee -7 of the Consultative Council for Postal Studies (CCPS), for implementation of the Washington General Action Plan under the UPU, and Chairman of the Standing Committee on Technical Cooperation and Assistance of the Asian Pacific Postal Union (APPU). As member of the CCPS, India is closely associated with various studies undertaken by CCPS. India, as Chairman of Committee-7 of the CCPS, is also a member of its Steering Committee. The Committee deliberates on the progress of various studies being conducted by the CCPS and guides its future course of action. India organised a Senior Postal Management Course for UPU member countries (18th November, 1991 to 14th December, 1991). Participants from Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, Fiji, Indonesia, Mynamar, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, Phillippines, Sri Lanka and Thailand attended the course.

The Department of Posts, plays an important role in the activities of the SAARC. Shri Vivek Kaul, Assistant Director General attended the 10th Meeting of the Technical Committee on Postal Services at Kathmandu (11-12 June, 1991). Shri S.S. Roy, Director, (Mail), attended a SAARC Study Tour "New Mail and Financial Services" organised by Pakistan in April, 1991. Shri Y.P.S. Mohan attended a Seminar on "Postal Operations and Future Challenges" of SAARC countries at Sri Lanka in June, 1991. A SAARC Workshop on "Caring for the Customers" was organised from 4-10 March, 1991 for the SAARC member countries at the Postal Staff College, India. Shri K.B.H. Nair, Principal, P.T.C. Saharanpur attended the Postal Security Course at U.S.A. in June, 1991 under the Consultancy Mission sponsored by the UPU. Shri Vineet Pandey attended a Practical Training Course and Study Trip on Electronic Mail at Bremen (Germany) from 28th October, 1991 to 8th November, 1991, under the Consultancy Mission sponsored by UPU.

POSTAL OPERATIONS

Introduction

The Postal Operation is often perceived as a single function of delivering letters from one end to the other. As a matter of fact, it is a chain of multifarious inter-related functions such as Registration, Money Order, Speed Post, Sale of Stamps, Postal Orders etc. The success of this operation is often dependent on the efficiency of other agencies in the Transportation Sector such as Airlines, Railways, Roadways, Shipping, etc. The Department of Posts also performs functions on behalf of other Ministries/ Departments e.g. Savings Bank and Postal Life Insurance; these are known as Agency functions.

Expansion of Postal Network

Rapid economic growth and social progress presupposes an efficient postal system. India has done well on this front and has one of the largest networks of Post Offices in the world. By 31.3.1992, there were 150346 Post Offices in the country. Of this, 134122 were in rural areas. A Post Office covered on an average an area of 21.9 sq. kms. and a population of 5827 as per the 1991 census. During 1991-92, 2068 Extra Departmental Branch Post Offices and 21 Departmental Sub Offices were sanctioned.

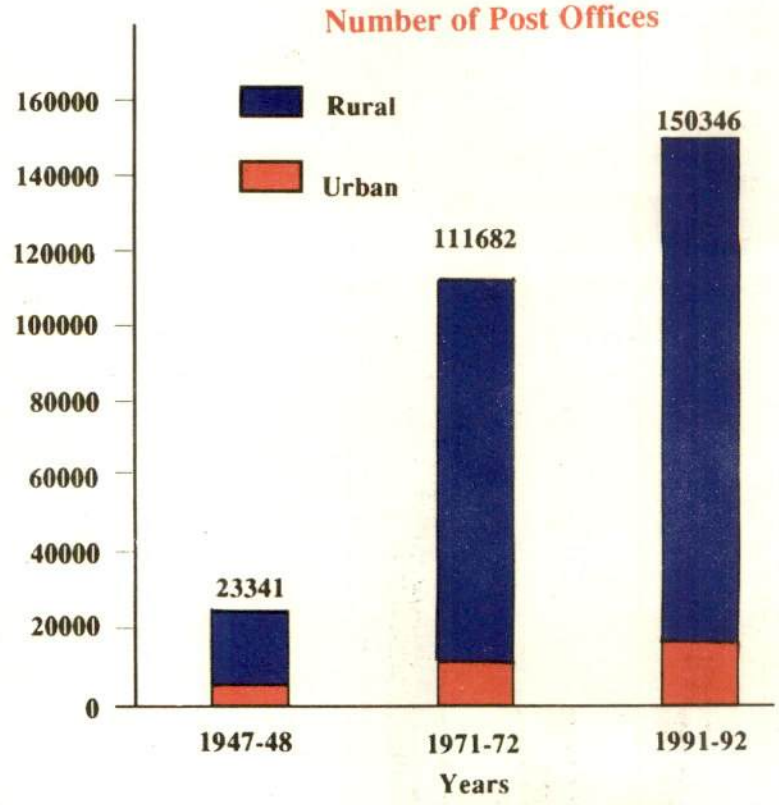

Services

The Post renders

Mail Services,
namely
Letters,
consisting of:
envelopes,
letter cards,
postcards
Book Packet

Newspaper Packet

Parcel

Classified as:
Ordinary Mail
Posting Certified-Ordinary Mail

Registration
Value - payable
Insurance
Speed Post

Money Transfer Services,
namely
Money Order
Postal Order

Other Services,
namely
Saving Bank
Postal Life Insurance
Telegraph
Telephone Public Call Offices
Telephone Revenue Collection
Passport Application Forms
Central Recruitment Fee Stamps

Postal Traffic since 1982-83
(Adjusted to Revenue)

(In Millions)

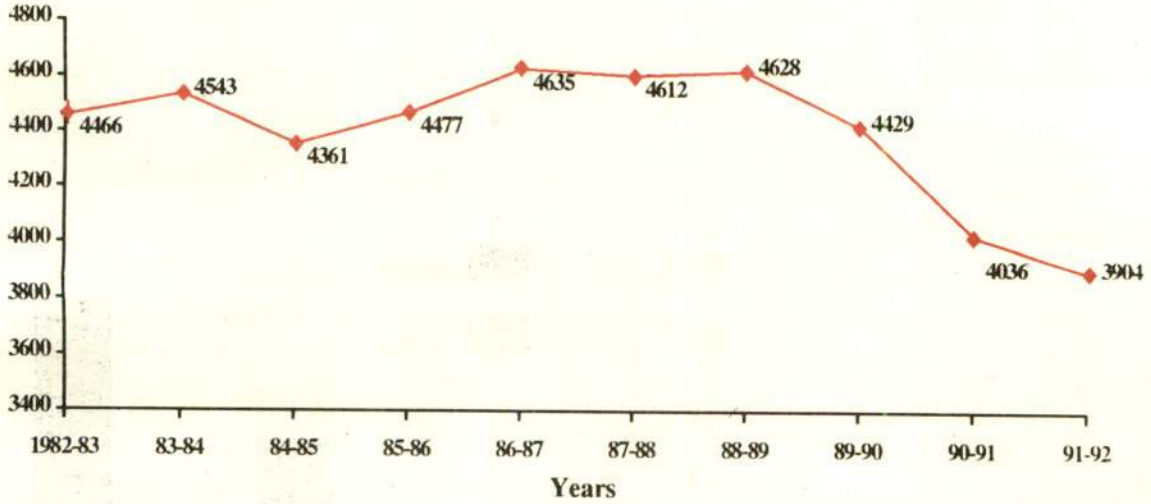

(In Millions)

Articlewise Postal Traffic

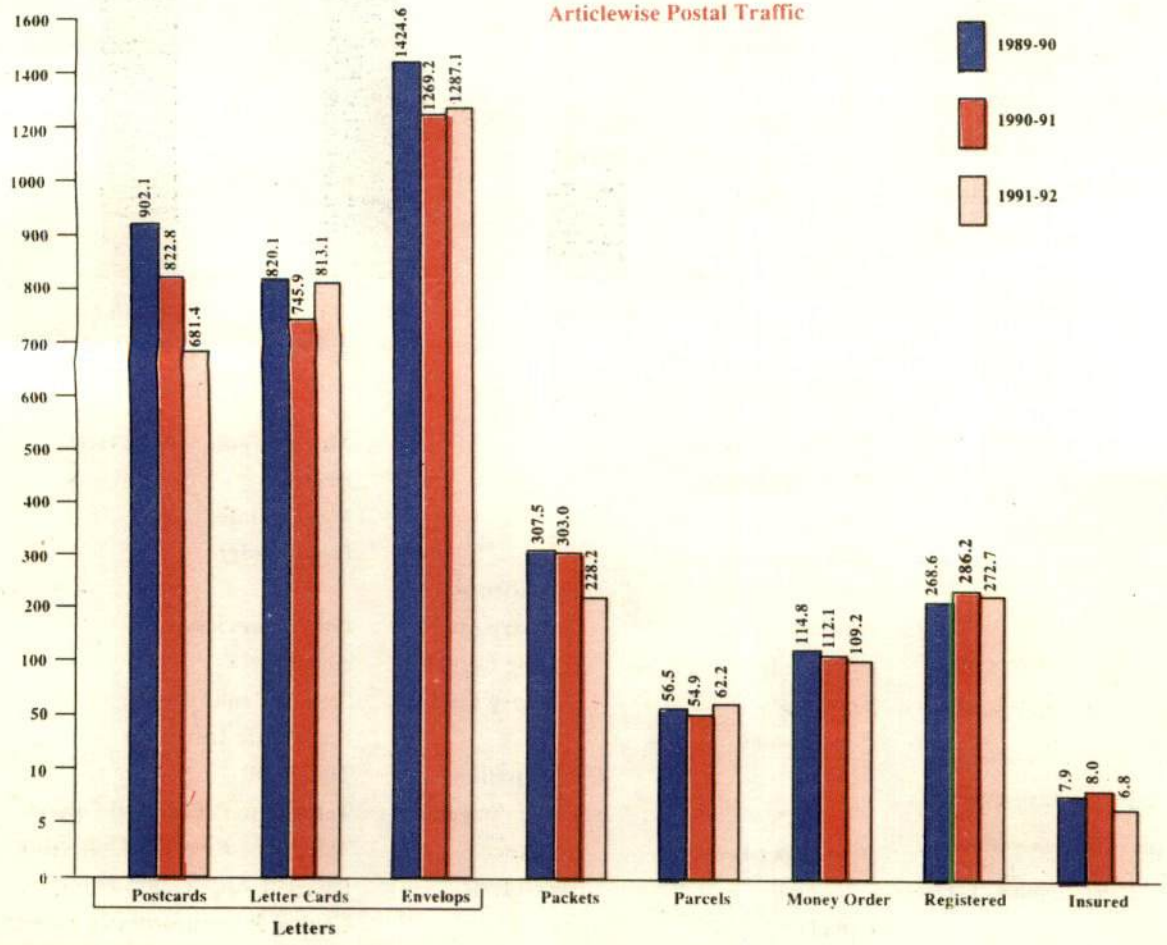

Mail Volume

Domestic unregistered mail handled during the year numbered 3191 million pieces consisting of 2716 million letters, 435 million packets and 40 million parcels. Domestic registered mail numbered 296 million pieces.

The Department of Posts conveyed 105.6 million remittances of money aggregating Rs.25872 million during the year through Money Orders. Remittances through Postal Orders totalled Rs.287.7 million.

Speed Post

In the year 1991-92 the number of Speed Post Extension Counters under national network increased with a counter opened at Gurgaon (Haryana) and 214 pairs of stations were added to the point-to-point Speed Post Service to cater tothe customers who need transmission of mails between specific pairs of cities. Similarly, personalised Speed Post Contract Service was extended to meet the demands of corporate customers with a vast network throughout India functioning through specific delivery arrangements. New International Speed Post links were established with Malawi, Cyprus, Canada, Ethiopia, New Zealand and Sudan w.e.f. 1.4.91.

During the year under review, Speed Post traffic registered a growth of 35.80%. The increase in Speed Post revenue was 59.71% over the previous year.

In the year 1992-93 Speed Post seeks to achieve (a) the establishment of computerised as well as manual track and trace system for providing immediate information/confirmation of delivery of articles, prompt dis-

Speed Post Traffic
(In Thousands)

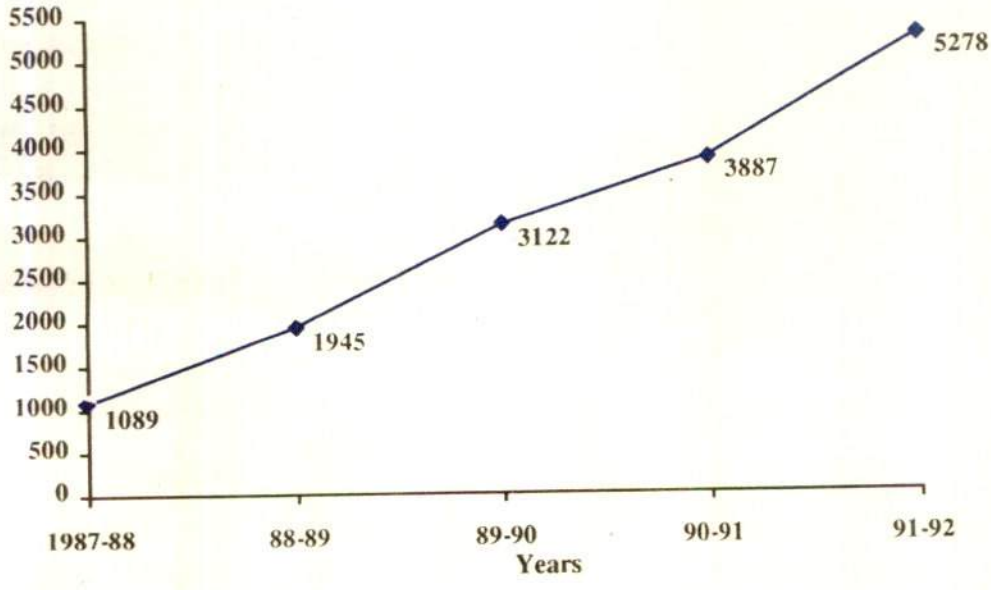

posal and redressal of complaints/refund claims and better customer relations, (b) Grant of full refund of Speed Post fee in the event of delayed delivery, (c) Delivery of Speed Post articles on Postal Holidays (not National Holidays), (d) Development of strategy for expansion of Speed Post network and (e) Use of standardised Speed Post forms by all the Speed Post Centres.

Technology Induction

Mechanisation of mail sorting has been one of the important areas for induction of technology in the Department of Posts. A project for mechanised sorting for inward and outward mail for the metropolis of Bombay was developed recently. On 1.1.92 an agreement was signed by the Department with Alcatel-Bell of Belgium for supply, installation and commissioning of the Automatic Integrated Mail Processing System. The machine is expected to be commissioned by the end of March, 1993.

On the basis of the experience and evaluation of PC Based Multipurpose Counter Machines installed last year, the Department decided to instal more such machines. Orders have been placed on two public sector companies in India for supply of 1000 more counter machines in Post Offices in various states.

In addition to these important areas, efforts are going on to identify other areas of postal operations where information technology can be gainfully utilised for improvement of services.

Mail Motor Service

A Departmental Mail Motor Service functioned in 90 stations in the country during the year under review. Twenty-one new vehicles were purchased to replace existing vehicles in order to improve the fleets and to maintain efficiency in transmission of mails.

The total fleet strength of the Mail Motor at the end of 1991-92 was 1103 and the fleet covered a total distance of 190 lakh kilometers.

System changes
Mail Box Scheme

The Department has been facing difficulties in organising delivery of mail in multi-storeyed buildings as they are increasing in number not only in big cities but also in medium sized towns. The Postman is subjected to the hardship of multiple stair cases one after another with all the mail he has to carry. This causes delay in delivery down the beat of the postman. It became necessary to effect a break with the tradition of delivering unregistered mail at every door, limiting it to the ground floor of multi storeyed buildings; those on other floors should provide a Mail Box on the ground floor, either for each individual or address separately, or for more than one address jointly. A statutory Order under Section 21 of the Indian Post Office Act was issued on May 29, 1991, bringing the following categories of mail within the scope of the order.

— Letter Mail, namely; envelope, inland letter card, post card and aerogramme
— Book, pattern, and sample packets
— Achnowledgement card
— Registered newspaper

The Order was to take effect on Jan 1, 1992. However, authority was vested in the Chief Postmaster General to continue delivery in the conventional manner at any station beyond that date if circumstances necessitated it.

Late Fee in Night Post Office

The Night Post Office is a special facility to the public. The Department incurs extra cost in operating Night Post Offices just for providing this additional facility. A late fee is collected for mail posted at Night Post Offices during certain hours. Late fee is now to be paid on unregistered as well as registered mail posted during the extended hours on week days and on holidays and Sundays. The scale of the fee is as laid down in the tariff structure from time to time.

Insurance of Postal Articles

The Limit of insurance was raised from Rs.10,000/- to Rs.20,000/- effective from Sept. 14, 1991.

Philately

Fifty one (51) Commemorative/Special Stamps were issued, including one on the 14th April, 1991 in honour of Dr. B.R. Ambedkar, and a commemorative stamp on the former

Outstanding Balances in all forms of Savings including Certificates (In Millions of Rupees)

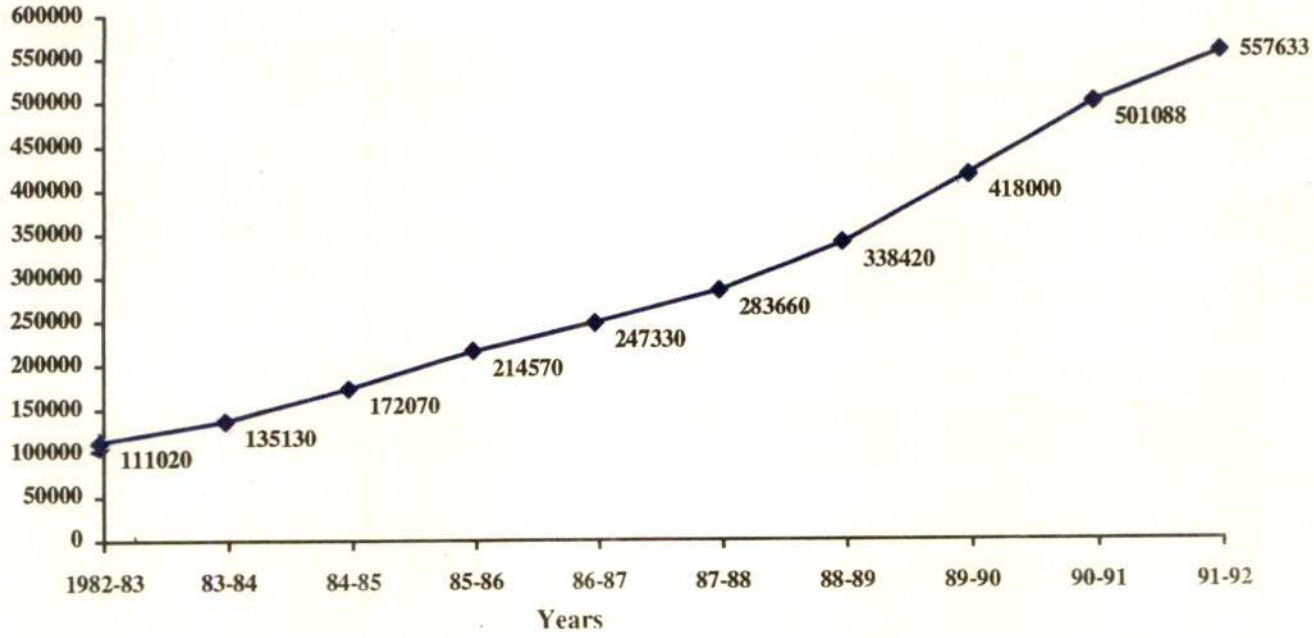

Prime Minister late Shri Rajiv Gandhi on 20th August, 1991. A set of four multicolour stamps was issued on tribal dances. The stamp on the Austrian composer Mozart drew popular appreciation. There are now fifty Philatelic Bureaux and 171 Philatelic Counters in the country for catering to the needs of Philatelists all over the country, the latest addition being the bureau opened at Raipur on 24.1.92.

The Department organised Circle level philatelic exhibitions during the year at Hyderabad, Andhra Pradesh and Patna, Bihar. At the international level, the Department participated in the exhibitions in Bangkok in August, 1991, Montreal in March, 1992, in Peru from 8th August to 29th August, 1991; and in Bonn from 21st October to 25th October, 1991.

Agency Services

Post Office Savings Bank

Post Office Savings Bank runs the following schemes on behalf of the Ministry of Finance:-

Savings Accounts
Recurring Deposit Accounts
Time Deposit Accounts
National Savings Accounts Scheme
Monthly Income Account Scheme
Public Provident Fund
Indira Vikas Patras
Kisan Vikas Patras
National Savings Certificates — 8th Issue

The Saving Bank Computerisation project has been initiated in the Head Post Offices of Delhi and it is proposed to extend it to selected Head Post Offices of important cities in the country during the Eighth Five Year Plan.

Postal Life Insurance

Postal Life Insurance offers the following four types of policies.

— Whole Life Assurance
— Convertible Whole Life Assurance
— Endowment Assurance
— Anticipated Endowment Assurance 15 years and 20 years.

Total Number of Policies
(In Millions)

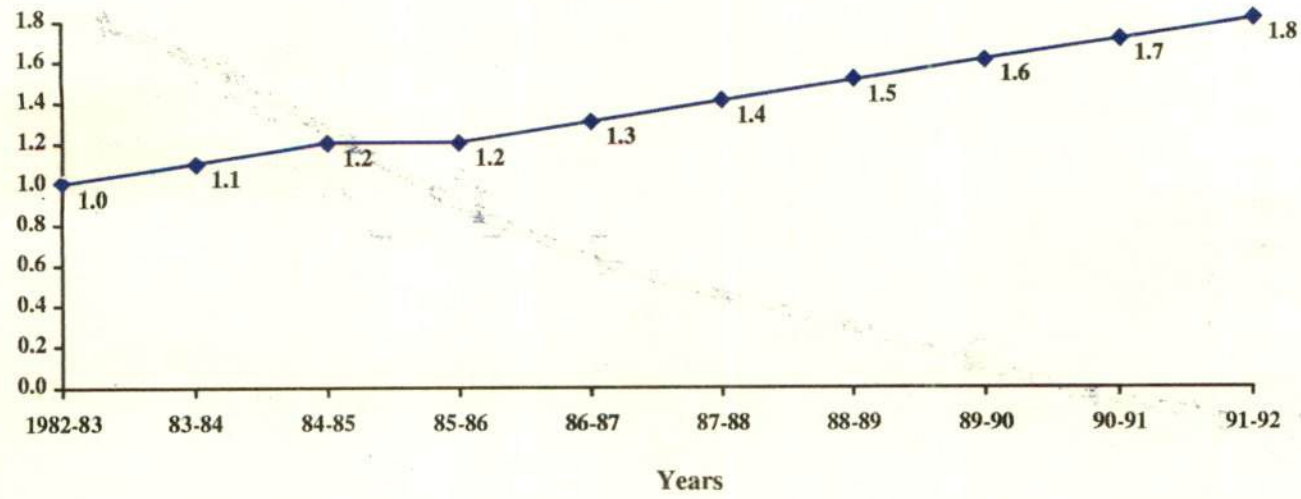

Total Sum Assured
(In Millions of Rupees)

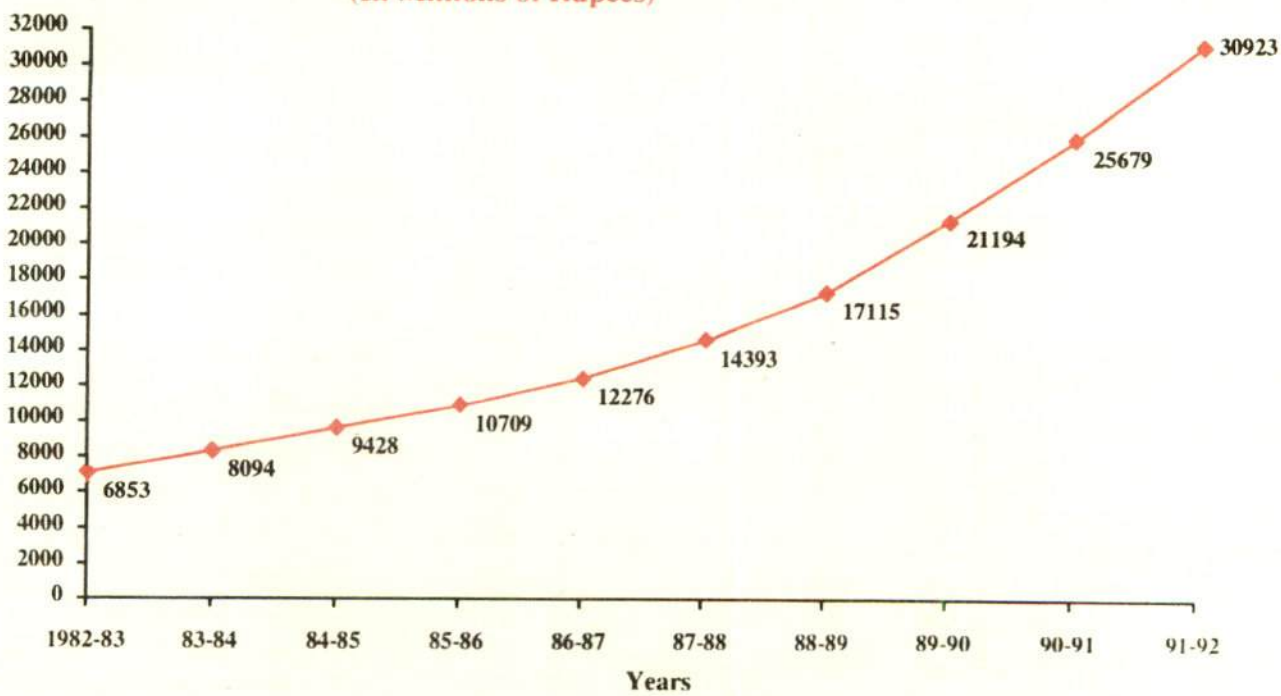

Life Insurance Fund
(In Millions of Rupees)

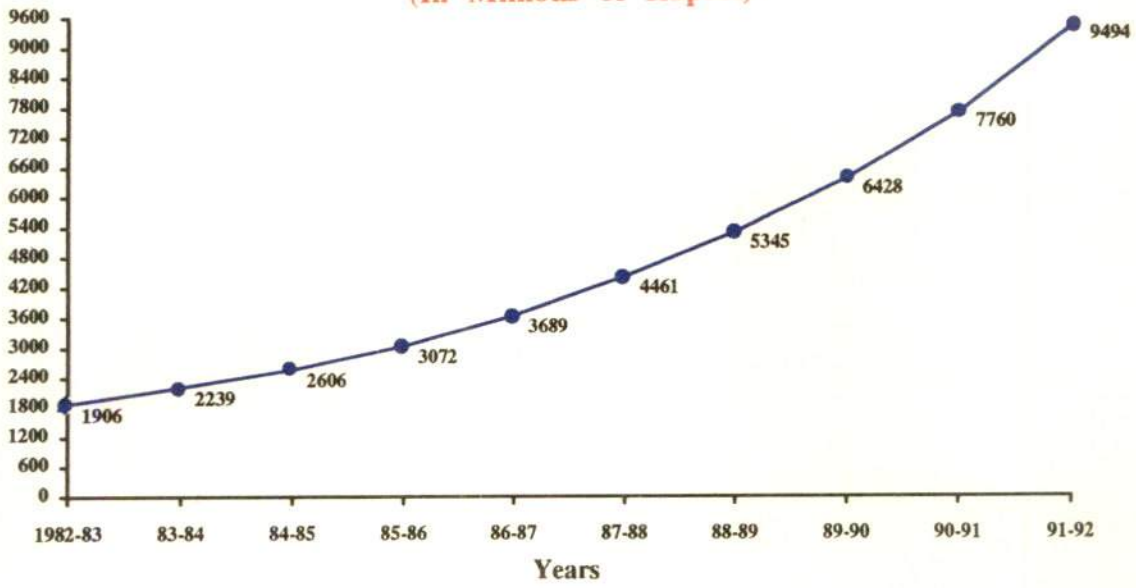

In 1991-92 business rose to 18,04,307 policies worth Rs.3092.34 crores compared to 16,91,754 policies worth Rs.2567.85 crores in the previous year. Gujarat Circle leads the rest with 2,68,559 policies as on 31.3.92. In 1991-92, new business of 1,59,959 policies was issued for Rs.558.48 crores compared to 1,56,358 policies for Rs.476.27 crores in the previous year. Gujarat & Karnataka Circles led the rest by procuring new business for Rs.115.68 crores and Rs.55.60 crores respectively.

The maximum limit of the sum assured was increased from Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakhs.

Customer Satisfaction

During the year, 669950 Public Complaints were received and enquired into as against 682599 complaints received in the previous year. The percentage of complaints to the total traffic handled is 0.00484% as against 0.00461% in the previous year.

Marketing and Commercial Publicity

The Department of Posts has adopted a market oriented approach to achieve customer satisfaction. A Marketing Division has been set up in the Directorate General of Posts to assess customers' needs and to strive to satisfy them by providing them the required services, to publicise the services already existing as also the new ones to be provided. A Corporate Identity Plan has been launched to brighten the image of the Department in the eyes of the public and our own employees.

The Department secured advertisements worth Rs1.30 crores through its Commercial Publicity Scheme. Thus there was an increase of Rs.73 lakhs over the revenue earned in 1990-91 from this scheme.

Returned Letters

The Department's 15 Returned Letter Offices which ultimately process undelivered mail, handled 31.2 million pieces of mail during 1991-92, 57% of them were further improved in their address and delivered to the addressees. 26% were returned to the senders after ascertaining their addresses.

Postal Premises

The Department spent a sum of Rs.29.89 crores on building activity during the year 1991-92. Out of this amount, Rs.27.72 crores were spent on construction of office buildings and staff quarters and Rs.2.17 crores on acquisition of land.

During the year 1991-92, the Department completed 82 office buildings, 203 staff quarters and one Inspection Quarter, and commenced construction of 82 office buildings, 169 staff quarters and 2 Inspection Quarters as new projects.

POSTAL FINANCE

The total revenue during the year 1991-92 was Rs.947.87 crores, registering an increase of Rs.107.02 crores (i.e. about 12.7%) against the preceding year's receipts of Rs.840.85 crores. This increase was due to better financial management and also partly because of upward revision of rates of Foreign tarrif with effect from Nov. 1, 1991.

The net working expenses during the year 1991-92 were Rs.1162.15 crores against the estimated expenditure of Rs.1175.00 crores projected in the RE 1991-92 representing a decrease of Rs.12.85 crores which is mainly due to implementation of strict economy measures. This was, however, greater by Rs.129.65 crores as compared to the actual expenditure of Rs.1032.50 crores in the year 1990-91. The increase was mainly due to payment of arrears of haulage charges to the Railways consequent upon the revision of rates with retrospective effect from 1.4.86, additional burden on account of higher rate of D.A. instalments sanctioned by the Govt. of India, and general price rise.

The expenditure — revenue gap of the Postal Services during 1991-92 was Rs.214.28 crores as compared to Rs.255.00 crores (R.E. 1991-92) and Rs.191.65 crores in 1990-91.

REVENUE AND EXPENDITURE 1991-92
(As compared to 1990-91)

(Rs. in crores)

Particulars	1990-91	1991-92	Percentage change over the previous year
REVENUE			
Sale of Stamps	511.66	569.91	11.38
Postage realised in cash	173.18	201.31	16.24
Commission on account of Money Orders and Indian Postal Orders	110.46	126.11	14.16
Other receipts	45.55	50.54	10.95
Total	840.85	947.87	12.72
EXPENDITURE			
General Administration	83.28	90.79	9.01
Operation	905.49	1042.76	15.16
Agency Services	46.31	54.84	18.42
Others	273.18	318.36	16.54
Total Gross Expenditure	1308.26	1506.75	15.17
Less Recoveries	275.76	344.60	24.96
Net Expenditure	1032.50	1162.15	12.56

The gross expenditure in important categories is given below:-

Pay & Allowances			
Contingencies and other items	1004.60	1104.57	9.95
Pensionary Charges	150.31	182.28	21.26
Audit & Accounts	30.88	33.30	7.83
Stamps & Postage etc.	34.77	38.81	11.61
Stationery & Printing etc.	23.41	27.38	16.95
Maintenance of Assets	1.49	7.35	393.28
Depreciation	5.40	6.00	11.11
Petty Works	1.48	1.68	13.51
Conveyance of mails (Payment to Railways & Airmail carriers)	55.92	105.38	88.45
Total	1308.26	1506.75	15.17

POST CARD

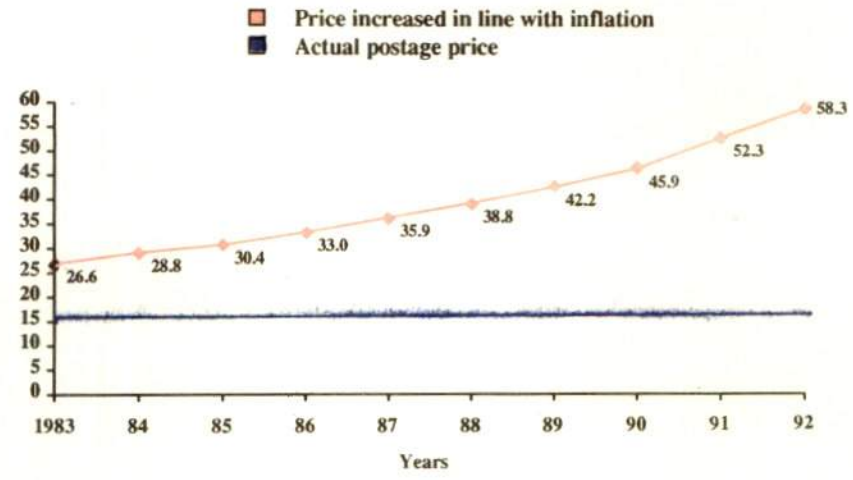

LETTER

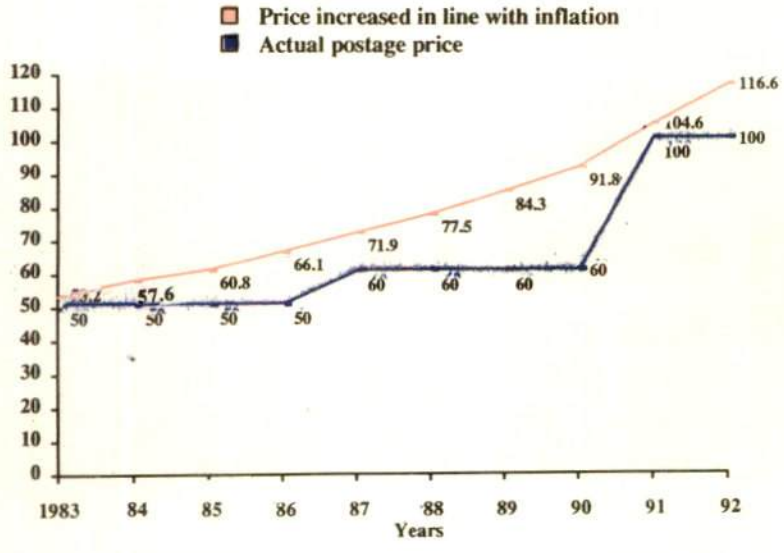

LETTER CARD

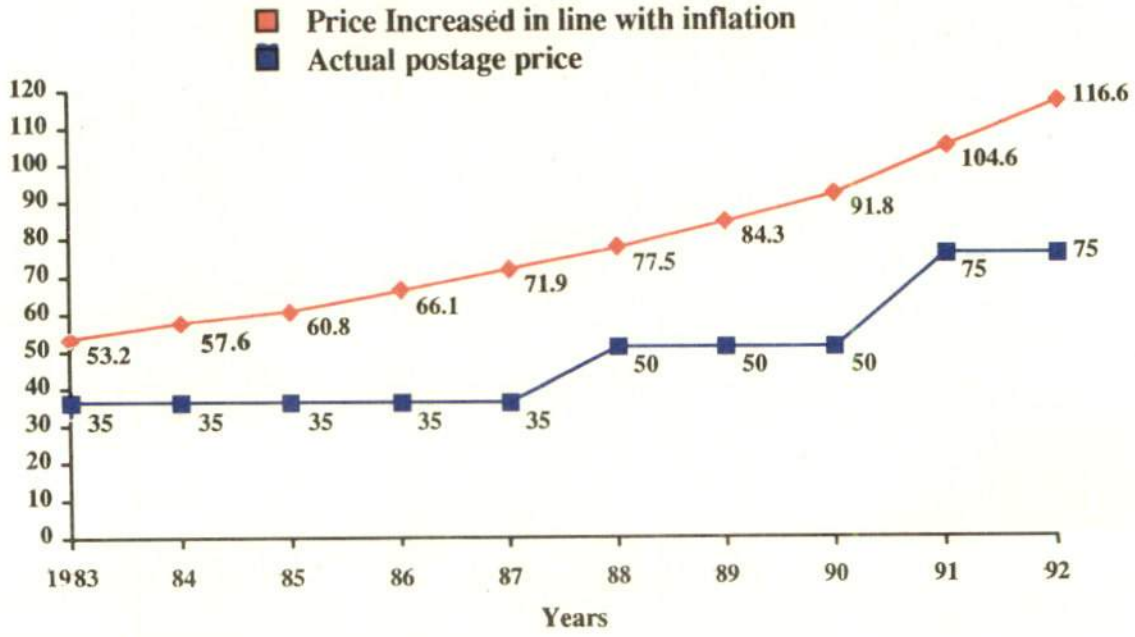

Revenue and Expenditure
(In Millions of Rupees)

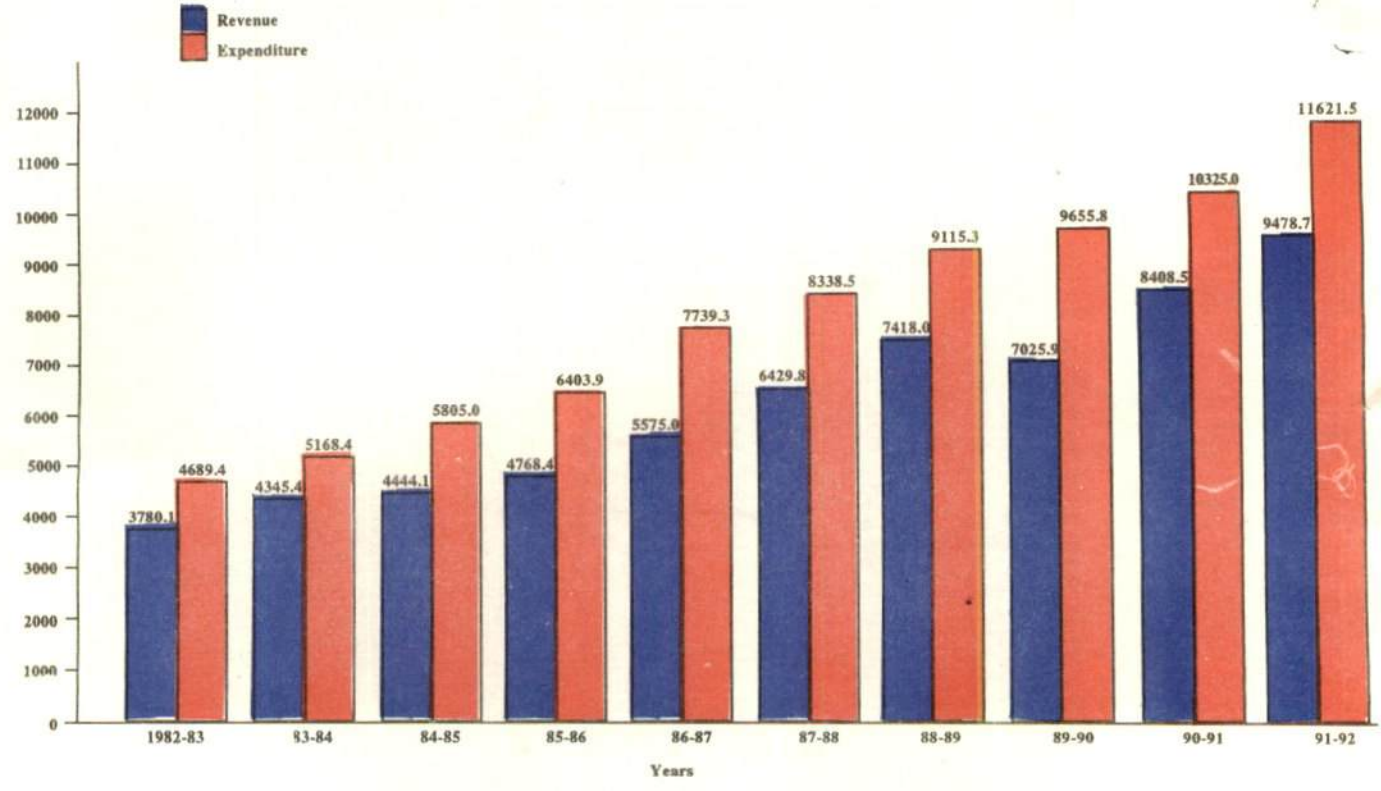

Cost of Service

The cost & revenue of main services for the year 1991-92 along with the position for the previous year are shown against each service below :

(Figures in Rupees)

Service	1990-91		1991-92	
	Cost	Revenue	Cost	Revenue
Postcard	1.17	0.15	1.25	0.15
Printed card	1.09	0.60	1.20	0.60
Letter card	1.28	0.75	1.41	0.75
Letter	1.29	1.81	1.43	1.81
Parcel	14.61	14.31	18.51	14.31
Money Order	11.51	8.99	13.16	8.99
Registered	8.20	6.00	8.76	6.00
Insured	10.77	18.12	12.66	18.12
Book Post				
Book Pattern and Sample Packet	1.58	2.42	1.78	2.42
Printed Books	1.96	2.26	2.25	2.26
Others	2.15	2.11	2.47	2.11

Agency Services

In the year 1991-92, the Department's recovery of working expenses on account of agency services was:

(Rupees in Crores)

Savings Bank & Savings Certificates	318.30
Postal Life Insurance	10.29
Payment of Railway Pension	4.08
Coal-Miners'/EPF Pension	8.31
Customs Duty realisation	0.99
Military Pension	0.11
Others	2.52
Total	344.60

Capital Outlay

The gross outlay on fixed assets in the year was Rs.33.20 crores, of which 91.4% was on land and buildings and 8.6% on apparatus, plants and others. Capital Outlay on fixed assets rose to Rs.458.02 crores at the end of the year. The net progressive capital outlay at the end of the year financed from General Revenues was Rs.372.80 crores.

HUMAN RESOURCES

Manpower

The personnel of the Department continued to be the principal resource for the Indian Postal System. The total staff strength as on 31.3.92 was 5.96 lakhs, including 3.05 lakhs Extra Departmental Employees who largely man the services in rural areas.

Training Programmes

The training infrastructure of the Department consists of (a) Postal Staff College of India, Ghaziabad and (b) Postal Training Centres at Saharanpur, Mysore, Vadodara, Darbhanga and Madurai.

The Postal Staff College of India conducts induction training programmes for officer recruits of the Indian Postal Service and the Indian P&T Finance and Accounts Service. In addition, it conducts Management/ Executive Development programmes and special courses for Postal Executives. It also runs programmes for officers of Foreign Postal Administrations under bilateral arrangements, or under the sponsorship of International Agencies like UNDP/UPU, etc. It conducted fifteen induction and in-service training courses during 1991-92. These included workshops on "Mail Transmission", "Postal Estates Management Training Programme" and "Management Appreciation Course on Public Relations and Marketing". Two important courses conducted for international participants were (a) UPU — sponsored course on "Senior Postal Management" held from 18.11.91 to 14.12.91, where 17 participants from 13 countries attended, and (b) Workshop on "Caring for the Customer" held from 4.3.92 to 10.3.92 and attended by 8 participants from 6 SAARC countries. The Postal Staff College India, Ghaziabad also adopted a mass tree plantation programme at the Campus to ensure a green and pollution - free environment.

The Postal Training Centres (PTCs) cater to the training needs of Inspectors/Supervisors/Postal Assistants/Sorting Assistants. Induction training programmes designed for employees elevated to higher management level are also conducted at these training centres. A total 14206 officials were imparted training during the year 1991-92 by the Postal Training Centres. Care is taken to impart training in Hindi and regional languages whenever possible.

Biennial Cadre Review

It may be recalled that in the year 1983, the Department had introduced the time bound one promotion scheme in its basic operative cadres. A scheme for ensuring second time bound promotion in the career of all employees in Group 'C' and Group 'D' operative cadres by the way of a biennial cadre review with the twin objective of increased job satisfaction and higher productivity was worked out and implemented during the year. The scheme covers approximately 35,000 Group 'C' and 9,000 Group 'D' employees.

The benefit of the Time Bound one Promotion Scheme was extended to SBCO staff with conversion of the LDC/UDC cadres into Postal Assistants, SBCO.

Staff Relations

The Department values the understanding and cooperation of its staff and is responsive to their perception of the management and its policies. This is an integral element in our plans for the development of the Department and for enrichment of its human resources. The Department has been involving its three Federations of employees' Unions and their constituents, and the non-federated Unions and Associations, in consultations and reviews of existing problems, and on framework approaches to the future.

The Department has healthy and meaningful relations with the three Federations and 27 Unions/Associa-

tions of employees and Extra Departmental Agents. Two meetings of the Postal Department Council (JCM) were held in addition to 11 meetings of its Standing Committee. A new Departmental Committee for Extra Departmental Agents was constituted and its first meeting was held in January, 1992.

SC/ST Employees

Reservation in favour of SC & ST candidates in appointments/promotions in the Department of Posts is done strictly in accordance with the relevant provisions in the orders of the Dept. of Personnel & Training.

Liasion Officers in field formations, as also a Liasion Officer in the Ministry, scrutinise all proposals for de-reservation with due care to ensure full observance of the relevant government orders. Due preference is also given to the grievances and complaints of SC/ST employees to ensure prompt redressal by the administrative branches/offices. During the period under review, 67 representations/ individual complaints were received and 57 of them have been settled.

Internal Work Study

— A Study for evolution of norms for sanctioning/creation of posts of SRMs, ASPs/ ASRMs/ Inspectors, LSG Supervisors and Postmen in "Speed Post" was completed and report submitted.

— A Study for uncovered items of work and evolution of norms for sanctioning group 'C' and supervisory staff connected with Franking Machines in Post Offices and 2nd office of posting completed.

— A Study for evolution of norms for sanctioning clerical staff in Mail Motor Units was completed.

— Work study of SCT Cell, CW (P) Section, DC Section, Inspection & O&M Section was carried out.

— Work Study for the review of norms i.e. the rate of out turn for Debit Checkers/Sorters in the Money orders Sections of the Postal Accounts Offices was completed and report submitted.

— Work Study for revision of norms for discharge of NSC in Post Offices was carried out.

— Work Study of Investigation Section, C.R. Section and PF Section of the Directorate was carried out.

— Staffing study in respect of Data Processing Assistants in the Director Postal Accounts, Madras.

Recognition of Higher Performance

The Dept. gives due recognition to employees who render meritorious services by honouring them with Meghdoot Awards.

The following employees were honoured with Meghdoot Awards for their outstanding and meritorious services in :-

1. Shri Mohal Lal, Extra Departmental Runner, Punjab.
2. Shri Krishan Lal-II, Inspector, Railway Mail Services, Punjab.
3. Shri U.A. Pathan, Driver, Gujarat.
4. Smt. Gandharwa Wati, Postal Assistant, Himachal Pradesh.
5. Smt. Kiran Garg, Postal Assistant, Delhi.

Staff Welfare

The Postal Services Staff Welfare Board remained active under the Chairmanship of Minister of Communications to promote, develop, organise and exercise overall control in respect of staff amenities and welfare, sports and cultural activities in the Department. The Board receives grants-in-aid for this purpose from Government Funds. Voluntary contributions from the staff and collections through sports and cultural activities are also arranged by the subordinate formations.

The funds of the Welfare Board are utilised for activities like sports, community centres, recreation clubs, financial assistance in cases of illness,

death and natural calamities, educational scholarships, subsidy for excursion trips, grants to help handicapped staff and their children, vocational training centres, creches, etc. During the year 1991-92, an amount of about Rs.90 lakhs was spent on welfare activities. Special relief measures were provided to the employees affected by the earthquake in Uttarkashi and adjoining areas in U.P. A grant of Rs.8 lakhs was paid from the Welfare Fund in addition to the grant provided by the Circle Welfare Fund, and the voluntary donations from the staff of other circles.

Rates of Scholarships and awards for school students were enhanced. Grant-in-aid to Creches, Tailoring Centres, Resident's Welfare Associations etc. were also enhanced. Fourteen Creches and 25 Tailoring Centres are operating with assistance from the Welfare fund. A Central Postal Ladies Organisation and corresponding Women's Organisations at the Circles are functioning to promote the interests of Women employees and dependents of the staff. These organisations are running creches, tailoring centres, dance and music classes. A Reading Room-cum-Library which was started for children of the staff in Kanpur under the aegis of the regional Postal Ladies Organisation has added a new dimension to welfare activities.

Holiday Homes

There are 19 holiday Homes for the benefit of the employees and their families.

Sports

All India Postal Services Tournaments in Volleyball, Table Tennis, Weightlifting, Powerlifting, Body Building, Aquatics, Athletics, Cycling, Football, Badminton, Kabaddi, Wrestling, Chess, Hockey & Basketball were held during the year. The All India Postal Cultural Meet was held at Nagpur in February, 1992. A number of sportspersons from the Dept. participated in national/international championships in various events.

Use of Hindi in Official Work

The Department, according to the Official Language Policy of the Central Govt., has been making concerted efforts to ensure maximum use of Hindi as Official Language at the Headquarters and also in the subordinate offices. Official Language Implementation Committees have been constituted at the Headquarters and at all Circle Headquarters and their subordinate offices for implementation of the Official Language Policy.

In keeping with the policy to promote implementation of Hindi through incentives and goodwill, various incentive schemes have been introduced in the headquarters and its subordinate offices for progressive use of Hindi. These schemes include 1. Akhil Bhartiya Dak Rajbhasha Shield, 2. Dak Vibhag Maulik Hindi Pustak Puraskar Yojna, 3. Awards for writing original articles in Hindi in 'Dak Patrika', 4. Dak Vihhag Rajbhasha Shield, 5. Incentive for original noting and drafting in Hindi, 6. Essay competition, 7. Hindi Elocution competition and 8. Hindi Quiz.

Part - 2
Annual Report
1992-93

Expansion of Postal Network

Expansion of Postal network in the rural sector continued. In order to ensure that the rural Post Offices should be set-up without any delay, Government delegated the powers for opening the Extra Departmental Post Offices to the Heads of Circles. This delegation has helped in prompt action and total number of Post Offices sanctioned upto Feb. '93 was 452. It was ensured that the Post Offices were opened according to the plan targets and the norms of the Government.

Speed Post

Speed Post was further strengthened by rationalisation of rate structure, proper publicity and marketing techniques. Speed Post Service has been introduced at Howrah (WB) w.e.f. Ist June, 1992. As on 31st December, 1992, 317 pairs of stations were in operation under point to point Speed Post Service in the country. International Speed Post links were established with Ghana, Hungary, Malaysia, Morocco, Uganda, Guyana, Denmark, Iran, Mexico, Niger, Panama, Papua New Guinea and Zaire w.e.f. Ist December, 1992.

Technology Induction

For quick transmission of money order advices, which will ultimately result in early payment of money orders, the Department prepared a project of M.O. transmission through Satellite. The first phase of the project involving installation of 75 Micro Earth Stations (VSATs) for this purpose has been approved by Government. For improvement of stamp impressions on Postal articles, action has been initiated for procurement of high quality stamp cancelling machines and machine made hand stamps.

Sale of Passport Application Forms

Department of Posts and Ministry of External Affairs have, together, introduced the sale of Passport application forms at all the Head Post Offices, numbering 834, and another 1038 Sub Post Offices in the country from Ist November, 1992. This arrangement has been made to ensure easy availability of the forms. As from January, 1993, Passport Offices and Post Offices will be the only sale points of Passport application forms.

Introduction of Delivery of Mail on Post Office Holidays.

Till 1982 fully-paid unregistered mail was delivered on post office holidays. It was given up that year. It was found from the experience of these years that sometime holidays fall consecutively or precede or follow Sunday resulting in no delivery of mail for more than one day at a stretch. This causes considerable inconvenience to people. To overcome this, delivery of fully paid unregistered mail on select holidays, so as to ensure that no two consecutive days, including Sunday, go without delivery of mail, has been introduced from Oct., 1992. There will however, be no delivery of mail on the three national holidays namely; Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanthi and on Sundays.

Limit of Value of VP Articles

Limit of Value of VP articles was raised from Rs.1000/- to Rs.2000- w.e.f. 30.6.1992.

Payment of Money Order by Army Post Offices

There are about 500 Army Post Offices serving purely the armed forces. Hitherto, Army Post Offices have been booking Money Orders, but not paying them. It has now been decided that Army Post Offices will also pay money orders like other Post Offices.

Relations with UPU

On a request from the Postal Administration of Bhutan, the Department of Posts has undertaken a Posts and Telegraphs Training Course for 15 Officials from Bhutan. The course is being held at Posts & Telegraphs Training Centre, Saharanpur, U.P. with effect from 1.12.92. The duration of the course is about 8 months.

This Department has decided to grant six fellowships to least developed countries under technical assistance in kind scheme to UPU. Under the programme it is proposed to conduct specialised course on areas like Philately, EMS, Mail Monitoring.

The Annual Session of the Consultative Council for Postal Studies (CCPS) of the Universal Postal Union was held at Berne, (Switzerland) from 12th October to 23rd October, 1992. The delegation led by Shri L.D. Bonnell, the then Secretary, Department of Posts, with Shri S.K. Parthasarathy, the then Member (Personnel) and now Secretary, Department of Posts, and Deputy Director General (International Relations) attended this Annual Session. Four Symposia on Human Resources, Research and Development, EMS and Postal Market formed an integral part of this CCPS Session.

Philately

New colours were introduced in the Postal stationery. Light Pink Colour and Light Grey Colour ILCs were introduced this year in addition to the regular blue shade ILC. Post Cards were also introduced in Light Sea Green and Light Blue colours in this year.

Two State-level Philatelic Exhibitions were organised during the period 1.4.92 to 31.12.92 i.e., Karnapex-92 in Mysore by Karnataka Circle from 11.9.92 to 13.9.92 and Rajpex-92 in Jaipur by Rajasthan Circle from 20.11.92 to 23.11.92.

The Department participated in the following International Philatelic Exhibitions during this period where the Indian Stamps were displayed and also sold:-

Granada-92 held in Granada from 24.4.92 to 3.5.92.

Expo-92 held in Chicago from 22.5.92 to 31.5.92 and

Kualalumpur-92 held in Kualalumpur from 1.9.92 to 7.9.92.

The following State level Philatelic Exhibition are proposed to be held during the period 1.1.93 to 31.3.93 :-

Kerapex-93 at Ernakulam from 16.1.93 to 20.1.93 and

Mapex-93 in Raipur from 4.2.93 to 6.2.93.

Meghdoot Award

The following Officials were selected for Meghdoot Award:-

Shri Raghuvir Singh, EDBPM, Haryana Circle,

Shri M.G. Ramanna, Postman, Karnataka Circle,

Shri R.K. Saxena, Postal Assistant, U.P. Circle,

Shri R. Ravindran Pillai, Asst. Supdt. of Post Offices, Kerala Circle, and

Shri Dhian Singh, Mailguard, Punjab Circle.

Heads of Circles Meet

The meeting of the Heads of Circles was held on the 29th and 30th July, 1992. This conference discussed number of major issues and took policy decisions. These decisions will form the basis for future operations of the Department.

Official Language

Two Hindi Workshops had been organised in the Directorate of Posts. With a view to create consciousness and accelerating the use of Hindi as Official Language, a Hindi Week was organised in the Directorate of Posts from 14th Sept. 92 to 18th Sept. 92. During the week various competitions were organised such as Hindi Noting and drafting, Hindi Elocution, Hindi Essay, Hindi Quiz, Hindi Stenography, typing competition etc., The participants who secured the first three positions in these competitions are proposed to be awarded. Hindi Day/Week was also celebrated in the Circles/fields offices of the Department during the period mentioned above.

During this period the Official Language Section of the Directorate had also prepared its own technical glossary and standard drafts billingually for the use of its officers and staff.

STATISTICAL SUPPLEMENTS

TABLE — 1

(Rupees in crores)

Financial Working	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (B.E.)
1. RECEIPTS	642.98	741.80	702.59	840.85	947.87	960.00
EXPENDITURE						
2. General Administration	68.67	72.91	80.25	83.28	90.79	105.00
3. Operation	754.22	775.64	864.29	905.49	1042.76	1057.33
4. Agency Services	32.81	38.47	44.07	46.31	54.84	58.40
5. Audit & Accounts	23.10	25.76	28.99	30.88	33.30	39.50
6. Engineering Maintenance	13.03	14.50	16.24	11.48	18.54	22.93
7. Amenities to staff	7.93	11.30	11.51	10.67	11.77	14.80
8. Pensionary Charges	96.34	99.89	110.18	150.31	182.28	176.50
9. Stamps, Stationery & Printing	30.36	46.61	62.07	63.16	66.19	74.70
10. Depreciation	4.36	4.87	5.19	5.40	6.00	7.50
11. International Cooperation	0.66	0.66	0.76	1.09	0.08	1.82
12. Social Security & Welfare Programmes	0.12	0.12	0.25	0.19	0.20	0.25
13. Gross working Expenses (Total of Items 2 to 12)	1031.60	1090.73	1223.80	1308.26	1506.75	1558.73
14. Less - Credits to Working Expenses	197.75	179.20	258.22	275.76	344.60	450.00
15. Net Working Expenses (Item 13 minus 14)	833.85	911.53	965.58	1032.50	1162.15	1108.73
16. Net Receipts (Item 1 minus 15)	(-) 190.87	(-) 169.73	(-) 262.99	(-) 191.65	(-) 214.28	(-) 148.73
17. Dividend to General Revenues	—	—	—	—	—	—
18. Surplus (+)/Deficit (-) (Item 16 plus 17)	(-) 190.87	(-) 169.73	(-) 262.99	(-) 191.65	(-) 214.28	(-) 148.73

TABLE — 2

Capital outlay during and upto the end of 1991-92

(Rupees in crores)

		During 1991-92	Upto the end of 1991-92
A.	**FIXED ASSETS**		
1.	Land	2.17	43.48
2.	Buildings	28.18	378.86
3.	Railways Mail Vans owned by Post Offices	—	8.61
4.	Apparatus and Plant	1.40	15.48
5.	Motor Vehicles	1.45	11.05
6.	Other Expenditure	—	0.54
7.	Gross Fixed Assets	33.20	458.02
8.	Deduct-Receipts and Recoveries on Capital Accounts	0.06	0.67
9.	Deduct-Expenditure met from Posts & Telegraphs Capital Reserve Fund	—	1.29
10.	Deduct-Amount of Contribution from Revenue	—	27.86
11.	Deduct-Depreciation on historical cost transferred from Revenue	6.00	52.02
12.	Total Deductions (i.e. total of Item 8 to 11)	6.06	81.84
13.	Net Fixed Assets (i.e. Item 7 minus 12)	27.14	376.18
B.	**OTHER ASSETS**		
14.	Cunsumer Co-operative Socities Share Capital Contribution	—	—
15.	Civil Engineering Suspense	(-) 0.70	(-) 3.38
16.	Total Other Assets (Items 14 Plus 15)	(-) 0.70	(-) 3.38
17.	Total Capital Outlay Financed from General Revenues (Item 13 plus 16)	26.44	372.80
18.	Deduct-Portion of Capital Outlay Financed from Ordinary Revenues	—	1.05
19.	Total Capital Outlay (Voted) (i.e. Item 17 minus 18)	26.44	371.75

TABLE — 3

Number of Post Offices as on 31st March, 1992

S.No.	State/Union Territories	Urban	Rural	Total	Area served by a Post Office (Sq. Kms.)
	STATES				
1.	Andhra Pradesh	1367	14847	16214	16.96
2.	Assam	286	3443	3729	20.91
3.	Arunachal Pradesh	9	257	266	314.66
4.	Bihar	716	10683	11399	15.26
5.	Goa	56	184	240	15.41
6.	Gujarat	821	7974	8795	22.13
7.	Haryana	313	2239	2552	17.24
8.	Himachal Pradesh	102	2507	2609	21.34
9.	Jammu & Kashmir	196	1382	1578	140.68
10.	Karnataka	1340	8364	9704	19.78
11.	Kerala	699	4272	4971	39.00
12.	Madhya Pradesh	1069	9985	11054	40.11
13.	Maharashtra	1393	10648	12041	22.55
14.	Manipur	35	588	623	35.31
15.	Meghalaya	30	431	461	48.59
16.	Mizoram	39	310	349	60.17
17.	Nagaland	19	260	279	59.13
18.	Orissa	592	7354	7946	19.63
19.	Punjab	450	3348	3798	2.53 *U 14.94 @R
20.	Rajasthan	851	9348	10199	33.53
21.	Sikkim	17	155	172	41.27
22.	Tamil Nadu	2043	10007	12050	10.78
23.	Tripura	47	631	678	15.33
24.	Uttar Pradesh	2104	17262	19366	15.20
25.	West Bengal	1095	7322	8417	10.53
	UNION TERRITORIES				
1.	Andaman & Nicobar	12	85	97	84.53
2.	Chandigarh	51	—	51	2.32
3.	Delhi	426	116	542	2.58
4.	Dadra & Nagar Haveli	5	40	45	6.70 *U 15.13 @R
5.	Daman & Diu	4	12	16	19.7
6.	Lakshadweep	—	7	7	3.2
7.	Pondicherry	37	61	98	4.62
	Total	16224	134122	150346	21.9

*URBAN @RURAL

TABLE — 4

SAVINGS BANK - Outstanding Balances

(Number in Lakhs)
(Amount in crores of Rupees)

	1987-88		1988-90		1989-90		1990-91		1991-92	
	No.of Account	Amount	No.of Account	Amount	No.of Account	Amount	No.of Account	Amount	No.of Account	Amount
Savings Bank	439	3403	450	3564	476	3766	647	3976	466	4376
CTD	52	560	57	499	67	383	83	270	77	202
Recurring Deposits	236	1545	283	1850	334	2255	385	2638	414	3094
Time Deposits	10	5745	10	4987	10	3830	12	2973	14	2861
National Savings Scheme	1	95	6	810	34	2516	30	4592	25	6755
Monthly Income Scheme	1	228	3	792	13	1535	13	2340	11	2720
Total	739	11576	809	12502	934	14285	1170	16789	1007	20008
Savings Certificates		16790		21340		27515		33320		35756
Grand Total		28366		33842		41800		50109		55764

TABLE — 5

Postal Life Insurance

Year	New Business		Total Business in force		Life Insurance Fund
	No. of Policy (in Lakhs)	Sum Assured (Rs. in crores)	No. of Policy (in Lakhs)	Sum Assured (Rs. in crores)	(Rs. in crores)
1982-83	1.05	108.4	10.07	685.3	190.6
1983-84	1.17	143.0	10.84	809.4	223.9
1984-85	1.12	153.0	11.56	942.8	260.6
1985-86	1.01	160.4	12.16	1070.9	307.2
1986-87	1.03	179.3	12.81	1227.6	368.9
1987-88	1.20	232.9	13.62	1439.3	446.1
1988-89	1.37	294.9	14.58	1711.5	534.5
1989-90	1.63	432.5	15.79	2119.4	642.8
1990-91	1.56	476.3	16.92	2567.9	776.0
1991-92	1.60	558.5	18.04	3092.3	949.4

TABLE — 6

PERSONNEL : Actual Strength (including those on deputation and training outside the department) as on 31.3.92.

A. GAZETTED			
Secretary (Posts)			1
Member, Postal Services Board			2
Secretary, Postal Services Board			1
Indian Postal Service			
Senior Deputy Director General/Chief Postmaster General			9
Senior Administrative Grade			78
Junior Administrative Grade			115
Time Scale			191
Postal Service Group 'B'			892
P&T Accounts & Finance Servic			1
Senior Administrative Grade			9
Junior Administrative Grade			20
Time Scale			656
Accounts Officers & Asstt. Accounts Officers			
Central Secretariat Service			67
Civil Wing			
Chief Engineer			1
Others			236
Other General Central Services			201
Total			2480
Non Gazetted	**Group 'C'**	**Group 'D'**	**Total**
Directorate	461	158	619
Post Offices	198590	33073	231663
Railway Mail Service	27438	19634	47072
Mail Motor Service	2177	652	2829
Others	3825	3039	6864
Total	232491	56556	289047
Total Departmental			291527
B. EXTRA DEPARTMENTAL			304568
Grand Total (A+B)			596095

TABLE — 7

Number of Employees - Scheduled Castes/Tribes as on 31-3-1992

	Scheduled Castes	Percentage to Total No. of Employees	Scheduled Tribes	Percentage to Total No. of Employees
Group 'A'	87	13.12	24	3.61
Group 'B'	193	10.62	39	2.14
Group 'C'	41740	17.95	13456	5.79
Group 'D' (Excluding Sweepers)	11022	19.82	3584	6.44
Group 'D' (Sweepers)	1030	81.42	206	16.28

54032 (7305

TABLE — 8

Number of Employees - Ex-Servicemen as on 31-3-1992

	Ex-Servicemen	Disabled Ex-Servicemen
Group 'A'	1	—
Group 'B'	1	—
Group 'C'	2123	87
Group 'D'	584	29

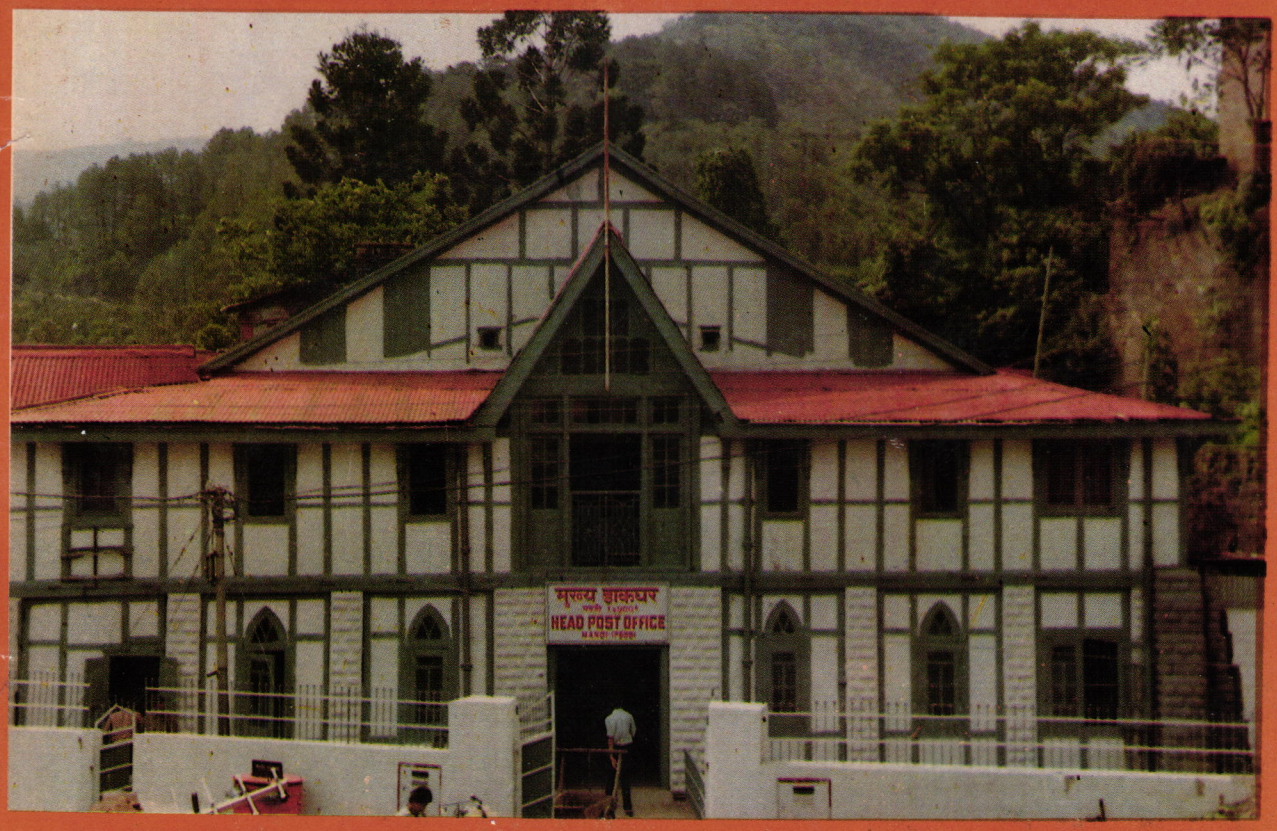

Mandi Head Post Office Building, Himachal Pradesh.

Postal Life Insurance work fully computerised at Bombay in April, 1992.

[illegible]ding Sui[illegible] Automati[illegible] [illegible] Mail Process[illegible] System,
[illegible] Sort[illegible] B[illegible]bay